साप्ताहिक

पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

समय माया

R.N.I. No.: MP/HIN/2006/20685

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

Webite: www.samaymaya.com
Email: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

Cell: +91 9425125569
Phone Fax: +91 731 2530859

(C) All Copyrights reserved with chief editor, do not publish any matter without prior written permission

In case of any dispute, may be solved only in Indore Court Jurisdiction

वर्ष 13 | अंक 49 | प्रति सोमवार इंदौर, 8 से 14 जुलाई 2019 | पृष्ठ 8 | मूल्य 2/- रुपए

देश को गुलाम बनाने की तैयारी

मध्यम वर्ग को निचौड़ा युवाओं को स्वरोजगार का कटोरा...

बहुराष्ट्रीय कंपनियों व पूंजी पतियों की रखैल मोदी का बजट 19-20, झूठे आंकड़ों की बाजीगरी

भुखेरा जन पार्टी ने अपने पूंजीपति मित्रों के बैंकों के डूबंत की भरपाई लिए रु 700 अरब करोड़, जाल साज नेता रूपी भू और कॉलोनी माफियाओं से मोटा कमीशन खाने उनका व्यवसाय बढ़ाने, पर रु 45 लाख तक के गृह ऋणो पर ब्याज में छूट। इस बजट का उद्देश्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मोटे लाभ के लिए यूरोप की तरह भारत की जनता को, छोटे व मध्यम व्यवसाय व व्यापारियों को, किसानों को, भारतीय संस्कृति के परिवारों को आड़े वक्त में बचत करने की सीख और प्रोत्साहन देने की अपेक्षा, बजट में दिए गए कर की छूट प्राप्त करने के लिए ऋणों में डुबो कर बर्बाद करने और गुलाम बनाने की है। देश के लोकसभा चुनाव 19 में, पूंजी पतियों बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रखेल भूखेरा जन पार्टी के महाधूर्त, आपराधिक, झूठे, फेकू मोदी और अमित शाह ने झूठ, छल, कपट से भारतीय प्रताड़ना सेवा के अधिकारियों को खरीद और ईवीएम की जालसाजी से पूनःसत्ता सत्ता हथिया ली। पिछले पंचवर्षीय कार्यकाल में आते ही उन्होंने पूंजीपतियों व बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए राष्ट्र के व्यापार उद्योग धंधों को बर्बाद करने अपने मोटे 25% कमीशन के लिए 100% निवेश की फुटकर व्यवसाय में छूट दे दी, काले धन के नाम नोट बंदी की , बाद में अत्यधिक उलझन भरा माल एवं सेवा कर थोप दिया गया। जिससे पूरे उद्योग धंधे छोटे दुकानदार पूरे तरीके से बर्बाद हो गये। स्वाभाविक है कि इस बजट में उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए महिला को वित्त मंत्री बना दिया गया ताकि देश की जनता सीधे गालियां मोदी और सीता रमन को न बक सके। बजट 19 में देश की मूलभूत आवश्यकताओं यथा नागरिकों के लिए, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पेयजल, बिजली, सड़कें आदि में कुछ को पूर्णतः नजरअंदाज कर दिया गया।

(शेष पेज 8 पर)

चीन दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी जो इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के माध्यम से दुनिया पर कर रहा जासूसी

दुनिया चीन का माल खरीदना करो बंद उसकी दादागिरी का करो अंत

चीन दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी जो इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के माध्यम से दुनिया पर कर रहा जासूसी। सभी विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सस्ते श्रम और कच्चे माल के चक्कर में सभी प्रकार का उत्पादन चीन में करना बंद कर देना चाहिए। उसके सस्ते माल के चक्कर में विश्व के अधिकांश देशों को अपने देश के लोगों को बेरोजगार कर लाखों उद्योगों को बंद करना पड़ा, जिसमें भारत पहले नंबर पर है। वही हाल यूरोप अमेरिका जापान आदि का भी हुआ। जिसकी साम्राज्यवादी नीतियां दक्षिण लाल सागर में और उसके चारों तरफ भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रूस, मंगोलिया, कोरिया, ताइवान, जापान, वियतनाम, मलेशिया, फिलिपींस, म्यांमार, आदि में जल थल और नभ के माध्यम से लगातार कि 50 सालों में चल रही हैं जिसे रोकने की सबसे बढ़िया उपाय यह है, कि दुनिया के सारे देश चीन का माल खरीदना बंद कर दें अपने आप उसकी अर्थव्यवस्था चौपट होगी अपने आप उसके साम्राज्यवादी हड़पोबादी और दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था को चौपट कर हड़पने की नीति अपने आप ठंडी पड़ जाएगी और उसे आज नहीं तो कल दुनिया के हर देश को मानना ही होगा।

दक्षिण और उत्तर पूर्वी एशियाई देशों में फिलिपींस इंडोनेशिया वियतनाम उसकी दक्षिण चीन सागर पर बढ़ती हुई दादागिरी के कारण भारी परेशान है ऑस्ट्रेलिया नेभी उसके प्रति बार-बार उसके विमानों को हमले के भय ने परेशान किया है जो उसके समुद्र में चीनी सामरिक नौकाओं के कारण बना हुआ है और नौकाओं में चीन ने मिसाइलें रडार आदि फिट कर रखे हैं। (शेष पेज 8 पर)

व्यापारियों, छोटे उद्योगपतियों को करना चाहिए जीएसटी के खिलाफ आंदोलन

जीएसटी ने तबाह कर दिया देश का व्यापार, उद्योग धंधे

भारत में पहली बार भुखेरा जन पार्टी की सरकार 1999 में आने के बाद 2004 तक रहने के कार्यकाल में, उनकी सभी मंत्रियों का उद्देश्य था कि जितना लूटा जा सके, देश के प्राकृतिक व मानव निर्मित संसाधनों को बहु राष्ट्रीय कंपनियों और पूंजी पतियों को बेचकर व गिरवी करके लूट लिया जाए अन्यथा कल हमारी सरकार रही ना रही परंतु धन पर्याप्त रहे ताकि भविष्य में आने वाले चुनावो में मतदाताओं को लुभाने, मीडिया को खरीदने जनता को भ्रमित करने

बड़े पूंजीपतियों, और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए तबाह किया जा रहा पूरा देश

में धन की कमी ऑडे ना आए। इसके लिए उन्होंने जनता को लूटने दुनिया की फुटकर व्यवसाय के राक्षस अकेले वॉलमार्ट से ही 5.5 हजार करोड़ डॉलर, अर्थात 3लाख 85 हजार करोड लेकर ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम जो सन 2006 में भुखेरा जन पार्टी के सांसदों के साथ मिलकर पास अवश्य किया। परंतु इसके पूर्व ही जिसकी छोटे व्यापारियों उद्योगपतियों से लेकर सड़क पर सब्जी भाजी बैठने वालों रोजगार करने और उनका धन्दा पानी छीनने और देश के खाद्य व्यवसाय पर मोटा लाभ कमाने के उद्देश्य से सन 2002 से रिलायंस ने रिलायंस फ्रेश के नाम से, बिरला, टाटा आदि।

(शेष पेज 2 पर)

एक देश एक चुनाव कदापि नहीं और कभी नहीं

वरना एक ही पार्टी सारे मिडिया और घोर भ्रष्ट चुनाव आयोग व उनके जिला स्तर पर बैठे भारतीय प्रताडना सेवा के अधिकारियों को मोटा लालच दे, खरीदकर इवीएम की जालसाजी के माध्यम से। लोकसभा और विधानसभाओं की सत्ता में आकर पूरे देश को देश की जनता देश के सार्वजनिक व मानव निर्मित स्त्रोतों को गुलाम बना देगी जैसा कि वर्तमान की भेड़ियों का झुंड पार्टी के अनपढ, घोर भ्रष्ट, झूठे, मक्कार मोदी ने रिजर्व बैंक और सभी बड़े बैंकों को जिसमें गरीबों का रू 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जमा था। कंगाल कर दिया। अपने पूंजी पतियों के लाभ और उनके ऋणों को माफ करने। उस भूखे भेड़िए ने 10 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर सड़कों पर राशन का एक रुपए किलो का गेहूं और रु.2 किलो का चावल खिलाकर रु 75000/- वार्षिक दे भिखारियों की तरह जिंदगी गुजारने के लिए छोड़ दिया जायेगा। अब उसकी निगाहें इस देश की लाखों हेक्टेयर उपजाऊ भूमि को मोटा कमीशन खाकर लाखों किसानों को बेरोजगार बनाकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंपने के लिए चूंकि उसके पास इवीएम के षडयंत्रों से जीते लोकसभा चुनाव में बहुमत पूरा है।

इसलिए कानून बनाकर अब किसानों की भूमि हड़पने का षडयंत्र रचा जा रहा है। ताकि यूरोप की तरह अपने बाप वॉलमार्ट, आईटीसी, रिलायंस फ्रेश हिन्दूस्तान लीवर जैसी राक्षस कंपनियां देश की भूमि पर कब्जा कर स्वामी किसानों को उसी की भूमि पर नौकर बनाकर यांत्रिकीय खेती कर आप की धरती पर उपजाया हुआ अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जियां, फल मसाले, आप उनको खाने और देखेंने तरस जाए। परन्तु वह उन उपजों से विदेशों में बेंच कर मोटा धन कमाए। (शेष पेज 2 पर)

साप्ताहिक समय माया

संपादकीय

मानवताहीन धन के गुलाम, सत्ता में गिद्धों का बसेरा

वह तस्वीर याद होगी आपको इसे नाम दिया गया था -छोटी भूख से मरती लड़की और गिद्ध इस तस्वीर में एक गिद्ध भूख से मर रही एक छोटी लड़की के मरने का इंतज़ार कर रहा है। इसे एक साउथ अफ्रीकन फोटो जर्नलिस्ट केविन कार्टर ने 1993 में सूडान के अकाल के समय खींचा था और इसके लिए उन्हें पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लेकिन कार्टर इस सम्मान का आनंद कुछ ही दिन उठा पाए क्योंकि कुछ महीनों बाद 33 वर्ष की आयु में उन्होंने अवसाद से आत्महत्या कर ली थी। ऐसा क्यों हुआ था? दरअसल जब वे इस सम्मान का जश्न मना रहे थे तो सारी दुनिया में प्रमुख चैनल और नेटवर्क पर इसकी चर्चा हो रही थी। उनका अवसाद तब शुरू हुआ जब एक 'फोन इंटरव्यू' के दौरान किसी ने पूछा कि उस लड़की का क्या हुआ? कार्टर ने कहा कि वह देखने के लिए रुके नहीं क्यों कि उन्हें फ्लाइट पकड़नी थी। इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि'मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि उस दिन वहां दो गिद्ध थे, जिसमें से एक के हाथ में कैमरा था। इस कथन के भाव ने कार्टर को इतना विचलित कर दिया कि वे अवसाद में चले गये और अंत में आत्महत्या कर ली। किसी भी स्थिति में कुछ हासिल करने से पहले मानवता आनी ही चाहिए। कार्टर आज जीवित होते अगर वे उस बच्ची को उठा कर यूनाईटेड नेशन्स के फीडिंग सेंटर तक पहुँचा देते जहाँ पहुंचने की वह कोशिश कर रही थी। केविन कार्टर में शर्म हया बची हुई थी, जिससे उसने आत्महत्या कर ली थी। मगर इन गिद्धो ने तो ईमान के साथ साथ आत्मा भी बेच खाई है। वर्तमान में भी पूरा देश की प्रशासनिक तंत्र का भारतीय प्रताड़ना सेवा व मीडिया गिद्धों की फौज का नाम बन चुका है।क्योंकि भेड़ियों का झुंड पार्टी की मोदी सरकार चारों तरफ देश के अंदर तबाही मचाए हुए है। देश के सारे घोर लालची भ्रष्ट व जालसाज प्रशासनिक बनाम प्रताड़ना सेवा अधिकारी व मीडिया के गिध्धों ने जनता के मोटे मांस रूपी मोटा धन और बड़े विज्ञापनों का धन हजम कर जनता को भ्रमित कर ईवीएम की जालसाजी से पुन: उसको सत्ता सौंप देते हैं। पर देश का मीडिया देश की बर्बादी होते हुए देखता हुआ शांत रहता है। देश को नीलाम होते और बेंचते हुए देख रहे हैं। ये सब भी उन्हीं गिध्दों की फौज है जो देश को मरता हुआ देखते हुए अपने मोटे धन के लिए उसका चित्रांकन कर जनता को भ्रमित कर रहा है। परंतु देश को बचाने के लिए सच की प्रस्तुति मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा। पर यह मोटे बेशर्मों की फौज को तो आत्मग्लानि भी नहीं होती। जिनकी आत्माएं मर चुकी है। जो धन प्राप्ति के लिए के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार हैं। अपने पद और उसके बल हर कदम दुरुपयोग करते हैं। आत्महत्या की तो सोच भी नहीं सकते। ये तो जनहितों और सच्चाई की लड़ाई लड़ने वालों, सच लिखने वालों को ही उल्टी बदतमीजी दिखाते हुए, भारतीय प्रताड़ना सेवा के, पुलिस के, न्यायालय के अधिकारियों कर्मचारियों से लेकर, अवैध काम करने वाले, व्यवसाई, उद्योगपति, भू, कॉलोनी, खनन माफिया, ठेकेदार, नेता मंत्री प्रधानमंत्री तक, उल्टे ही अपने पद और सत्ता का दुरुपयोग करते हुए उन्हें डराते धमकाते और हतोत्साहित करते हैं। यहां तक की देश का घोर भ्रष्ट जाहिल आपराधिक प्रवृत्ति का तानाशाह प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अपने अपराधों को कुकर्मों को छुपाने, दबाने, प्रसार माध्यर्मो, सोशल साइट्स, व्यक्तिगत संचार माध्यर्मो की निगरानी करने कानून बनाते हैं, सत्ता के छल बल का दुरुपयोग कर, लो की निगरानी जासूसी करते हैं। यहां तक कि अपने कड़वे सच का प्रचार-प्रसार होने पर सरकारी कानून पुलिस और न्यायालयों का दुरुपयोग कर ये हाथ वाले मानवीय गिद्ध उन सच बोलने, लिखने वालों को प्रताड़ित करने, गिरफ्तारी करने, कारागार में भेजने से लेकर उनकी हत्या करने में भी आगे रहते हैं। अर्थात देश के आम 100 करोड़ लोगों के चारों तरफ गिद्धों का ही साम्राज्य है।

जिला पंचायतें मुख्य कार्यपालन अधिकारी से लेकर नीचे संविदा पर बैठे बाबू चपरासी तक

घोर भ्रष्ट, जाल साज, डकैतों का अड्डा, 10-10 वर्षों से 99% संविदा कर्मी एक ही स्थान पर

सारे मोटी चमड़ी के घोर भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी, ग्राम पंचायतों के सरपंचो व पंचों के साथ मिलकर 80 से ज्यादा योजनाओं में करते हैं भारी लूटपाट। यही कारण है कि सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर जानकारी की तो दूर, अपीलों को भी खारिज कर दिया जाता है। क्योंकि मुख्य कार्यपालन अधिकारी अपीलीय अधिकारी भी है अपनी ही जिला पंचायत का, लोक सूचना अधिकारी भी है। मध्य प्रदेश की जिला पंचायतें सबसे बड़ी सरकारी भ्रष्टाचारी और हरामखोरी का अड्डा बन चुकी है। केंद्र व राज्य सरकार की ग्रामीणों के विकास की लगभग 80 से ज्यादा योजनाओं में प्रदेश की सभी जिला पंचायतों में आने वाले के मिलने वाले अरबों रुपए के धन मैं कैसे लूटपाट की जाती है। यह जिला पंचायतों में खुले में देखा जा सकता है। जिनसे पैसा मुख्य कार्यपालन अधिकारियों जो कि जनपद पंचायतों मैं बैठे होते हैं से लेकर ग्राम पंचायतों के सरपंचों, सचिवों तक में बंटता है। स्वाभाविक है, कि दो नंबर के भ्रष्टाचार के धन से ग्राम पंचायतो के सरपंच सचिवों रोजगार सहायकों तक के दिमाग सातवें आसमान पर होते हैं। अपनी नीच हरकतों के चलते गांव के वो कुछ खास लोगों को ही वह सुविधाएं देकर बाकी के नाम पर पैसा हजम करके अपने कार्यों की इतिश्री कर लेते हैं। सन 2000 से लेकर सन 2018 तक अकेले शौचालय के नाम पर पूरे देश में देश की 6.4 लाख गांवों और लगभग 700 शहरों में लगभग रुपए 5 लाख करोड़ खर्च कर दिया गया। अकेले मध्य प्रदेश के 54 हजार गांव में पिछले 18 सालों में 25 लाख से ज्यादा शौचालय का निर्माण हुआ। जिसका 40लाख शौचालय का लगभग 2 हजार करोड कागजों पर हजम कर लिया गया। इसमें भी 3योजनाएं है इसके अंतर्गत निर्मल भारत स्वच्छ व अभियान के अंतर्गत सामूदायिक शौचालय, के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को एक ही स्थान पर 5से 15 शौचालय का निर्माण करना था, 90% गांवों में पता ही नहीं है। व्यक्तिगत स्तर पर इसके अंतर्गत पिछले 18 वर्षों में कागजों पर, ग्रामीणों के घरों में 5से 7 शौचालय निर्माण कर दिये। शाला के अंतर्गत प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं मैं शौचालय निर्माण करना था, यही हाल 81 योजनाओं में आने वाले पिछले 18 सालों में सभी योजनाओं का 50 से 70% पैसा जो लाखों करोड़ में था प्रदेश की 22816 ग्राम पंचायतों, 249 नगर पंचायतों 96 नगर पालिका, 14 नगर निगम, कागजों पर ही निर्माण कार्य और उन्नति दिखाकर हजम कर लिया गया। यह एक छोटा सा उदाहरण है। जबकि इंदिरा आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, मनरेगा, महिला बाल विकास, कृषि एवं उद्यानिकी, ग्रामीण यांत्रिकीय, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के अंतर्गत ही पाइप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना क्रमांक 65 ग्रामीण नल जल योजना का संधारण कमांड क्र. 64, हैंडपंपों क्षतिग्रस्त प्लेटफॉर्म का निर्माण क्र 66, नल जल योजना का संधारण एवं मरम्मत क्र 24, हैंडपंप का संधारण एवं एवं मरम्मत आदि में भी ग्रामीणों के पेयजल की व्यवस्था की जाती है। जबकि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग इस संबंध में जब कार्यपालन यंत्री देवास के बोरना से इस संबंध में कई बार बात की गई कि ग्राम अजनास की जिसे 16 वीं लोकसभा की विदेश मंत्री रही श्रीमती सुषमा स्वराज ने इस गांव को गोद लिया था। 2017 में तो उन्होंने कन्नौद और बागली के उपयंत्री के नंबर देकर बात करने को कहा परंतु वर्ष 2018 में कार्यपालन यंत्री बोलना कब सीधा कहना था कि हमने अजनास गांव की पूरी ग्रामीण नल जल योजना को पूरा करके ग्राम पंचायत को दे दिया है। पर जब वहां के सचिव से बात की गई। तो उसका कहना था, कि हमने ऐसी कोई भी लिखित योजना के संबंध में पूरी होने ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकार करने के संबंध में नहीं दिया है। क्योंकि हमने सबसे पहले योजना की पूरी डीपीआर मांगी थी। जो हमें आज तक नहीं दी गई। जिससे हम जानना चाहते थे की कहां कितनी लाइन बिछाई गई कितनी स्वीकृत थी। कितने बॉल्व कहां इस तरीके से लगाए गए हैं पानी कहां से कितना आएगा कितना जायेगा इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है इसलिए हमने योजना को ग्रहण करने से मना कर दिया। इसके विपरीत उन्होंने हमें चलाने और जलापूर्ति करने के लिए कहा, इसलिए हम अस्थाई तौर पर ग्रामीण आबादी को पानी देने के लिए कर रहे हैं। जहां जहां मुख्य अधिकारी के रूप में महिलाएं बैठी होती है। वहां की जाल साज घोर धूर्त और मक्कार भ्रष्टाचार से पैसा तो दोनों हाथों से लूटकर खाती है काम के नाम पर बहाने, कभी भी 12:00 बजे से पहले समय पर कार्यालयों में न आना, अगर लेन-देन में मोटी वसूली है। तो सारा धन इन्हें चाहिए और काम की बात हो तो अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पर डाल कर बहाने बनाकर गायब हो जाती है यह हाल केबल इंदौर देवास की जिला पंचायतों का ही नहीं जनपद पंचायतों, महिला बाल विकास, इंदौर ग्रामीण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, वाणिज्य कर आदि पूरे देश और प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, निगमों, पालिकाओं, आदि का है। वरिष्ठों पुरुष अधिकारियों से शिकायत करने पर जवाब मिलता है भैया 12:00 बजे क्या 5:00 बजे भी आएंगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और ऑफिस नहीं भी आएंगी तो भी उनका वेतन उनके घर पहुंचाने के लिए सिर के बल जाना पड़ेगा। वरना उनके पास तो कानूनी हथियार है। किसी पर भी छेड़छाड़ का आरोप लगा दो उसकी जिंदगी तबाह कर दो। फिर हमारी तो क्या जिले के कलेक्टर की, मंत्री की और मुख्यमंत्री की औकात नहीं की उनसे कोई पूछताछ करें या कुछ कहे । काम करें तो ठीक नहीं करें तो ठीक। जनता को अगर आप को तकलीफ है। तो आप जानो। चाहो तो हमारी शिकायत कर दो पर हमसे कुछ नहीं बोल सकते जनता का पैसा जालसाजी, भ्रष्टाचार में सबसे ज्यादा महिला अधिकारियों को चाहिए। सूचना के अधिकार को तो यह सब देखती सुनती भी नहीं। चाहे राज्य सूचना आयोग कितने भी आदेश दे।

जीएसटी ने तबाह कर दिया देश का व्यापार, उद्योग धंधे

पेज 1 का शेष

बहुराष्ट्रीय कंपनियों जिसमें इंडियन टोबैको कंपनी जोकि ब्रिटिश टोबैको कंपनी की शाही कंपनी है और आजादी के पूर्व से भारत में कार्यरत है, की जिसने किसानों की फसल पर कब्जा करने के लिए हरियाली के नाम से अपने बड़े-बड़े खरीदी बिक्री के मालस जिला मुख्यालयों के बाहर मुख्य सड़कों पर खोल दिए थे, उनके जालसाज अधिकारी मंडी गए किसानों को ज्यादा भाव का लालच देकर वहां से माल के साथ उठा लाते हैं। ले आने के बाद, उनका माल मंडी से कम रेट पर खरीदकर, उन्हें नगद भुगतान करने की अपेक्षा उनके मालस में पड़ा हुआ सामान खरीदने के लिए विवश करते हैं।

इसके साथ ही उसने सन 2012 तक उसके विज्ञापन के अनुसार 15 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर कब्जा कर लिया था। हिंदुस्तान लीवर, दुनिया की सबसे कुख्यात वॉलमार्ट कंपनीयों के फुटकर बाजार पर मोटे कमीशन के बदले कब्जा करने के लिए खुला छोड़ दिया गया था। देश के अधिकांश राज्यों के विद्युत मंडलों की कंपनियां बना दी गई थी। बड़े बड़े सरकारी उद्योगों का विनेवेशीकरण के नाम पर 10 से 20% धन शासन के खाते में जमा कर बाकी अरुण शौरी और स्व. प्रमोद महाजन जैसे घाघ गिद्धों ने 20 -30% बांटकर 50% स्वंय हजम कर लिया। इन सबसे से बच जाने के बाद में भी यदि फिर भी देश के छोटे व्यापारी उद्योगपति बच जाए और व्यवसाय संचालित करने से ना माने तो उन्हें अत्यधिक विवादित नासमझ आने योग्य शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान करने वाले ऐसे कर बसूली के कानूनों के जाल में उलझा दो! जिन्हें वो कभी समझ ना सके। और बदले में उसका आर्थिक सामाजिक और नैतिक पतन करने के लिए गिरफ्तारी कर, उसे बर्बाद कर दो ताकि वह अपना व्यवसाय बंद करने के लिए बाध्य भी हो जाए। इससे अपने आप पूंजीपतियों बहुराष्ट्रीय कंपनीयों को जो मोटा लाभ होगा उसका 25% लाभ का हिस्सा सीधा सत्ताधीश राजनीतिक पार्टियों को मिलता रहेगा। इसी उद्देश्य के लिए यह जीएसटी कानून भुखेरा जन पार्टी ने इस देश के व्यापारियों उद्योगपतियों पर कानून के माध्यम से धीमी मौत देने के लिए थोपा।

जिसके बारे में समय माया समाचार पत्र लगातार सन 2006 से इसकी सच्चाई जो यूरोप में सामने आ रही थी लिख रहा था पर तब लोगों को समझ में नहीं आया। अभी भी वक्त है, देश के सारे व्यापारी एकत्रित होकर, अपना रोजगार, देश की स्वतंत्रता बचाने इसके विरुद्ध आंदोलन करें जीएसटी कानून को हटाने, या अधिकतम एक बार 14% कर उत्पादक पर लगाने, 2रे, 3रे, 4थे स्तर पर, बिक्री के जाने पर उस कर की वसूली आधी अंतर पर लगाई जाए, न की, दूसरे, तीसरे, चौथे स्तर पर माल की बिक्री लागत में, पूरा टैक्स दिया जाकर, पूर्व में दिए गए टैक्स की वसूली की जाए। कानून को अत्यधिक सरल बनाया जाए। जब व्यापारी उत्पादक माल की बिक्री पर तत्काल कर वसूली करके सरकार को ऑनलाइन जमा कर रहा है। तो महीने के अंत में, उस माह की बिक्री, लोटे हुए माल का को घटाकर विवरण दिया जाए। उसका व्यापार रोकने बर्बाद करने का षड्यंत्र सरकारी तौर पर, पूंजीपतियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मोटे लाभ के लिए तत्काल बंद किया जाए। देश की जनता के द्वारा चुनी और बनाई गई सरकार देश के लिए काम करें पूंजीपतियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए नहीं।

नगर निगम इंदौर में पिछले 5 वर्षों में किए गए हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार

बैठी है कदम-कदम नेता अधिकारियों कर्मचारियों की गिद्ध फौज

महापौर, निगमायुक्त, इंजीनियर, अधिकांश पार्षद, अधिकारी, कर्मचारी घोर भ्रष्ट जाल साज और लुटेरे करोड़पति हैं। यदि हर कदम निगम के कार्यों की बारीकी से जांच की जाए तो 90% नेता अधिकारी-कर्मचारी सलाखों के सरकारी बंगले में रहेंगे। सभी बंदरबांट में जुटे हों। चारों तरफ नेताओं के दलालों का बोलबाला हो। तो कौन किसके बारे में कहेगा और बताएगा। सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर वहां बैठे जाल साज हरामखोर अधिकारी आवेदकों को जानकारी देने की अपेक्षा भूल जाते हैं। उलझाते हैं। अपील में जाने पर यहां वहां दौड़ाकर परेशान कर दिया जाता है। भोपाल के आवेदक श्री भारद्वाज को तो जवाब में साफ लिख कर दिया गया नगर निगम जानकारी देने के लिए बाध्य् नहीं। क्योंकि जन धन यहां बैठे सूकरों की फौज के बाप की जागीर है। कानून, घोर भ्रष्ट, जाल साज, डकैत महापौर, निगमायुक्त और अधिकारियों कर्मचारियों की रखैल। जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे।

इंदौर नगर निगम ने रुपए 280 करोड़ का ठेका 16 पंछियों और 70 किलोमीटर पाइप लाइन बिछाने का लगभग 25३ कमीशन पर देश की कुख्यात राम की कंपनी को सौंपा है जिसने पीथमपुर में सन 2006 में रु. 800 के अनुदान के लिए 60 एकड़ जमीन पर 25 करोड़ रुपए का कचरा निपटान केंद्र बनाने का सहमति पत्र मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण विभाग के साथ हस्ताक्षरित किया था। उसे 60 एकड़ जमीन एकेवीएन द्वारा दी जानी थी जमीन की उपलब्धता मात्र 20 एकड़ थी स्वामी था परियोजना की लागत भी एक बटे तीन 8.33 करोड़ की हो जानी चाहिए थी। परंतु उसने टीपीआर के अनुसार प्रोजेक्ट तैयार ही नहीं किया और केवल गड्ढे खोद दिए और आप उसमें वह यूनियन कार्बाइड का मिक गैस का कचरा भी दबा रहा है। इस प्लांट में महाराष्ट्र गुजरात और मध्य प्रदेश की फैक्ट्रियों का घातक रसायन युक्त जहरीला कचरा भी दबाया जा रहा है और उस पर मिट्टी डालकर पौधारोपण करने का नाटक किया जा रहा है और उसके बदले में करोड़ों रुपए साल की मोटी कमाई कर रहा है यह है नीच गिद्धों का समूह।उसने नर्मदा घाटी में भी दो-तीन ठेके लिए परंतु उनमें भी सालों के बाद में 20-25% काम ही किया। अग्रिम लेकर हजम कर गया। इंदौर नगर निगम में बैठे घोर भ्रष्टों की फौज जिसमें जल आपूर्ति एवं निकासी अधीक्षण यंत्री पीसी जैन, कार्यपालन यंत्री संजीव श्रीवास्तव, निगमायुक्त आशीष सिंह, महापौर मालिनी गौड़, संभागायुक्त आकाश त्रिपाठी पूर्व और वर्तमान कलेक्टर लोकेश जाटव व अन्य अधिकारियों ने मिलकर इस घोर भ्रष्ट जालसाज कंपनी को 280 करोड़ का ठेका सब कुछ जानने के बाद में भी दे दिया।

अब वह कंपनी जो 16 पानी की टंकियां बना रही है।उसमें इस तरह जंग लगा साधारण लोहे की छड़ों से कांक्रीट के खंभे खड़े करके 2-2 लाख लीटर की टंकियों का निर्माण किया जा रहा है। जहां पर हार्ड टॉर सरिए का उपयोग किया जाना था। जैसा कि पार्षदों से जानकारी प्राप्त हुई। स्वाभाविक है की मोटी कमाई करने उन टंकियों की जिंदगी 5 से 10 वर्ष से ज्यादा नहीं होगी और उनके गिरने टूटने फूटने पर भारी जनहानि होगी।

दूसरी तरफ 70 किलोमीटर पाइप लाइन बिछाने में डाली गई पाइप के लोहे की मोटाई भी डीपीआर के अनुसार नहीं है उन पाइप लाइनों के अंदर बाहर सीमेंट की या अन्य रसायनिक तत्वों की मिलाकर कोटिंग नहीं की गई है जिससे वह अंदर पानी की और बाहर मिट्टी की जंग से सुरक्षित रहकर लंबे समय तक कार्यरत रह सकें।

दूसरी तरफ सड़कें खोदने पाइप लाइन डालने निगम की मशीनों का ही उपयोग किया जा रहा है। इसके बाद में उनका पुनः सीमेंटीकरण और सड़क का निर्माण

पुनः दी गई हालत में करने के नाम पर भी यह कंपनी ने पाइप बिछाकर पूरे शहर की 70 किमी सड़कों को खोद मारा। बनाने के नाम पर उसने वही मिट्टी जो खुदाई में निकली थी।

पलटा कर छोड़ दिया वहां अब गहरे गड्ढे हो गए और निगम अपने पैसे से उन सड़कों पर इस भरी बरसात में केवल चूरी भराई व बिछाकर छोड़ रहा है। इसमें भी मोटी कमाई की जा रही है निगम के इंजीनियरों और पार्षद व अधिकारियों द्वारा। परंतु यह हरामखोर शूकरों की फौज कंपनी से बदले में मोटा कमीशन खाकर जन धन से उस कार्य को पूरा करवा रही है। लगभग 1 महीने से उन खुदी सड़कों पर वाहन फंस व गिर रहे थे। पलट रहे थे और दुर्घटनाग्रस्त होकर लोग चोटिल हो रहे थे। लोगों ने जब हल्ला मचाना शुरू किया तो इन्होंने जन धन से उस कार्य को काम चलाऊ बारिक गिट्टी की करके छोड़ा जा रहा है।

सबसे ज्यादा पैसा नगर निगम में अपनी झूठी वाह वाही और मिडिया के दैनिक समाचार पत्रों इसमें भास्कर, पत्रिका, राज, नई दुनिया, अग्निबाण, प्रभात किरण, नवभारत, अपनी दुनिया, जैसे 30 से ज्यादा दैनिक, साप्ताहिक, अपनी लूट, भ्रष्टाचार, जालसाजियों की कहानी न छापे के लिए करोड़ों रुपए के विज्ञापन पिछले 5 साल में हर साल बांटे गए। दूसरी ओर सफाई नंबर वन के नाम पर भी अपने खास लोगों को पूरे शहर की खाली दीवारों पर सफाई के विज्ञापनों के नाम पर रु. 5 -7 प्रति वर्ग फुट की पेंटिंग को रुपए 50 से 80 ठेके में दी गई और जनता का करोडो रुपए हजम कर लिया गया।

हर वर्ष सड़कों के सीमेंट करंट डामरीकरण के नाम पर रु 200 करोड़ से ज्यादा बर्बाद किया गया जिसमें लगभग रु50करोड़ केवल झूठे बिल वाउचर से कागजों पर ही भजन किया गया। जबकि 70% सड़कों अनावश्यक सीमेंट की सड़कों पर ज्यादा कीमतों पर डामरीकरण करके पैसा हजम किया गया किसी भी निर्माण, मरम्मत रखरखाव आदि में जिसमें सड़कों, नालियों भवनों मनचाहे तरीके से विधायकों महापौर पार्षदों व अन्य अपनी पार्टी के लोगों को बिना कानूनी ई टेंडरिंग निविदा विज्ञापन आदि की कानूनी प्रक्रिया पूरी किए बिना ही अंधों की तरह रेवड़ी बांटकर जनधन की बंदरबांट मचती रही।जो जितना बड़ा नेता उसको उतने सारे काम उतना मोटा कमीशन हजम करता रहा।उसमें नेताओं के पट्ठे ठेकेदारों ने मोटी चांदी काटी। निसंदेह पैसा नीचे से ऊपर तक बाबू चपरासी से लेकर महापौर निगम आयुक्त सब ने हाथ साफ किए।

400 से ज्यादा वाईफाई टावर लगाने में हजम किया गया लगभग रु200करोड जो औचित्यहीन सिद्ध हुआ और जनता का पैसा डूब गया। जिसमें लगभग रुपए सो करोड कमिशन हजम किया गया जबकि वाईफाई स्तंभों का वर्तमान में कोई उपयोग ही नहीं रहा क्यों की जिओ, एयरटेल आइडिया की 400/- से 500/- में 3 माह की असीमित इंटरनेट की और बातचीत करने की सुविधाओं ने मुफ्त की वाईफाई की उपयोगिता ही खत्म कर दी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वाईफाई टावर लगाना बंद नहीं किया गया जनता के धन की बर्बादी लगातार अपने मोटे कमीशन के लिए की जाती रही।

निगम के अंतर्गत बाग बगीचों के निर्माण विकास के नाम पर भी सैकड़ों करोड़ का हर वर्ष भ्रष्टाचार किया जाता है। जिसका एक नमूना असलम नाम के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को पकड़ा जाने के बाद जनता के सामने आया है। इसमें भी सभी का मोटा महापौर, निगमायुक्त, उपनिगमायुक्त से लेकर, इंजीनियर, उद्यान अधिकारी सबकी जालसाजी पूर्ण भूमिका सामने आने के बाद भी किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई जबकि लूटपाट जालसाजी में सभी हिस्से दार हैं।

सफाई के नाम पर लगभग 10000 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों का वेतन कहीं ठेके पर कहीं सीधे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के रूप में हर महीने भुगतान किया जाता है। जिसमें 3000 से ज्यादा फर्जी कर्मचारी जो नेताओं के खास पट्ठे और चेले हैं। बिना काम के ही भुगतान दिया जा रहा है। यह फर्जीवाड़ा पिछले 40 साल से चल रहा है। बेशक इस सब में भी मोटा कमीशन वहां बैठे बाबुओं से लेकर, पार्षद जोनल अधिकारी, अकाउंटेंट लेखाधिकारी आदि सबका बंधा हुआ है। इसलिए सब चुप रहते हैं।

मध्य प्रदेश के जाने-माने इंदौर शहर में पुराने शहर में नालियों के निर्माण तो फिर भी ढंग से बने हुए थे परंतु 1970 के बाद बने पूरे नये शहर में खुली व भूतल के नीचे नालियां निजी कॉलोनियों से लेकर इंदौर विकास प्राधिकरण, मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल की कॉलोनियों में भी मुख्य मार्गों और गलियों तक में भी नहीं बनाई गई थी। जिनके बनाने के नाम पर हर साल सीमेंट की सड़कों की और भवनों के पीछे की खुदाई करके नालिया बिछाने के नाम पर लगभग रुपए 200 से 300 करोड़ हजम किए जा रहे हैं सन 2000 से। यहां तक की जैएनआरयूएम, विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक, नाबर्ड तक से सैकड़ों करोड़ का ऋण लेकर काम करवाया गया परंतु सारा ही काम स्तर हीन बिना नियोजन के हुआ।

भवनो के निर्माण की अनापत्ति प्रमाण पत्र और नक्शा स्वीकृति में भी वहां वर्षों से कुंडली मारे बैठे इंजीनियरों, बाबूओं में भारी लूटपाट चलती है। अनेकों बार शिकायत होने के बाद भी वहां बैठे इंजीनियर बाबूओं को वहां से हटाया नहीं गया बार बार ऑनलाइन घोषणाएं होने के बावजूद भी वे निगम के सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ करके भवन निर्माण की नक्शों की स्वीकृति में अडंगे डालकर, बिना वसूली किए स्वीकृति 6 महीने तक नहीं देते।

शहर के चारों तरफ झुग्गी बस्ती की साफ सफाई के नाम पर लगभग रु2000 करोड़ से ज्यादा की बहुमंजिला भवनों की मनचाहा तरीके से मोटे कमीशन पर स्तरहीन निर्माण कार्य करवाया गया जिसमें दरवाजे खिड़किया आवंटन से पूर्व भी सडने गिरने लगे थे। फिर आवंटन में बंदरबांट मची और अपने खास लोगों और वोटरों को अपने हिसाब से मोटे कमीशन पर वह मकान फ्लैट आवंटित किए गए। सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर वहां बैठे जाल साज हरामखोर अधिकारी आवेदकों को जानकारी देने की अपेक्षा भूल जाते हैं उलझाते हैं।

अपील में जाने पर यहां वहां दौड़ाकर परेशान कर दिया जाता है। भोपाल के आवेदक श्री भारद्वाज को तो जवाब में साफ लिख कर दिया गया नगर निगम जानकारी देने के लिए बाध्य् नहीं। क्योंकि जन धन यहां बैठे सूकरों की फौज के बाप की जागीर है। कानून, घोर भ्रष्ट, जाल साज, डकैत महापौर, निगमायुक्त और अधिकारियों कर्मचारियों की रखैल। जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे।

महीना पहुंचाओ और जो चाहो जैसा चाहो खोद के ले जाओ

खनिज माफिया के इशारे पर नाचता है खनिज व पूरा राजस्व विभाग

पूरे प्रदेश में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद खनिज नीति बदले जाने की तैयारी चल रही है। जो पूर्व की सत्ता में भुखेरे श्वानों को जिसको जहां मिले जैसा मिले लूटो खाओ। की नीति पर चल रही थी। प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज ही प्रदेश का सबसे बड़ा रेत माफिया था।जिसने 200 किलोमीटर नर्मदा नदी के दोनों तरफ अपने 700 डम्फरो से लगातार नदी के सीने को खोखला कर रेत निकाल कर पूरे भोपाल संभाग और इंदौर संभाग में बेची। इसके लिए उसने आसानी से रेत का उत्खनन नदियों से करने, उसमें कानूनी उलझन पैदा ना हो इसलिए रेती को पंचायती राज के अंतर्गत सौंप दिया था।इसलिए रिपोर्ट म प्र शासन के खनिज विभाग का नियंत्रण समाप्त हो गया था। वैसे तो खनिज विभाग में खनिज परिवहन करने वाले डम्फरों, ट्रकों, ट्रैक्टरट्रालीयों का भी पंजीयन किया जाता है। पंजीकृत किए वाहन ही जारी किये गये परमिटों पर ही वर्णित खनिज का निर्धारित अवधि में निश्चित दूरी तक परिवहन कर सकते हैं।इंदौर में कोयला, रेती, पत्थर, मिट्टी, मुरम आदि का 90% व्यापार अवैध रूप से ना केवल वरन् सरकारी क्षेत्र में भी होता है।

जिसकी मोटी कमाई जो लाखों रुपए प्रतिदिन में होती है। संबंधित जिले के निरीक्षक दोनों हाथों से करते रहते हैं और उसका हिस्सा जिला खनिज अधिकारी, उप जिलाधीश, जिलाधीश की आदि को पहुंचता रहता है। अवैध उत्खनन के मामले में, अधिकांश भुखेरा जन पार्टी के नेता भू माफिया रेत माफिया उत्खनन माफिया लगातार 15 साल तक रेती, गिट्टी, पत्थर, जैसी सामान्य गैर खनिज पदार्थों से लेकर, कोयला, माइका, तांबा, लोहा आदि के अयस्को से लेकर छतरपुर पन्ना की हीरे की खदानों से हीरे तक निकाल कर बेंचते रहे।

रेती, गिट्टी, मुरम, या कच्ची चट्टानों की टुकड़ी जो सड़क बनाने भवनों की नींव की भराई करने आदि में काम आती है पत्थर जो निजी स्तर और शासकीय कार्यों में निर्माण सामग्री का अति आवश्यक हिस्सा है। वर्तमान में मोटी कमाई का स्त्रोत बन चुका है। जिसका सरकारी स्तर पर शासन का खनिज विभाग राजस्व विभाग के अंतर्गत ठेके आवंटित करता है। शासन के इस खनिज विभाग मे जिला खनिज अधिकारी और निरीक्षक जो इंदौर, उज्जैन, धार, देवास, शाजापुर में बरसों से कुंडली जमाए बैठे हैं। जो खनन माफियाओं की कठपुतली बन मोटा पैसा वसूल कर शासन को केबल 20 से 30% की और रॉयल्टी हाथ लगने देते हैं। जिसकी कहानी किस्से आए दिन अखबारों में छपते रहते हैं परंतु उन अधिकारियों और निरीक्षकों का कोई बाल भी बांका नहीं करता क्योंकि उसमें पटवारी, तहसीलदार, सहायक व उप जिलाधीश से लेकर जिलाधीश का भी मोटा हिस्सा होता है। इसके कानूनी पहलू और कागजों की हेरा फेरी में घाघ बाबूओं का जो 20-30 वर्षों से ज्यादा समय से एक ही स्थान पर जमे ठेकेदारों के साथ मिलकर शासन को मिलने वाली रॉयल्टी में, अपना मोटा हिस्सा डकार कर भारी हेराफेरी करवाते हैं।

प्रदूषण फैलाओ मंडलः पीथमपुर कचरा निपटान केंद्र- पूर्ण जालसाजी

दफनाया जा रहा यूनियन कार्बाईड का 2600 टन जहरीली गैस का मलबा

मंडल सचिव मिश्रा से लेकर नीचे तक सब जुटे हैं वसूली में, पीथमपुर की फैक्ट्रियों के जलवायु प्रदूषण से 10 किलोमीटर ब्यास में हो रही खेती की जमीन और भूजल बर्बाद

इंदौर के निकट पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र यहां पर प्रदूषण फैलाने वाली सैकड़ों इकाइयां हैं। इन सब के विपरीत 6 जून 2006 को उद्घाटित किया गया। रामकी हैदराबाद की सबसे बदनाम कंपनी जो अनेकों शाखाओं में काम करती है। घोर भ्रष्टाचार स्तरहींन, लापरवाही पूर्ण तरीके से काम के लिए पूरे देश में कुख्यात है। यहां रू 25 करोड़ की लागत से 60 एकड़ भूमि में कचरा निष्पादन केंद्र जिसमें मध्य प्रदेश प्रदूषण मंडल का केन्द्र का आठ करोड़ का अनुदान था। जिसमें कई सतहों के नीचे खतरनाक स्तर के कचरे को जलाकर दबाने की बात की गई थी।परंतु मुझे खबर लग जाने के कारण उस दिन बुलाई गई सर्वजनिक स्तर की सभा में भी मैं पहुंचा। उस समय यह बात सामने आ चुकी थी कि उसे एकेवीएन इंदौर ने मात्र 20 एकड़ जमीन दी है।तो उसकी लागत भी 8 करोड़ ही रह जानी थी। परंतु उस समय के तत्कालीन मंडल का अध्यक्ष और सचिव ने मिलकर उस बात को उठने ही नहीं दिया और राम की कंपनी को रु. 8 करोड़ का अनुदान सन 2010 तक दिलवा दिया गया। इस सम पीथमपुर से लगे हुए गांव की पहाड़ी पर इस कचरा निपटान केंद्र को बनाना था। उस पहाड़ी पर से बहने वाला पानी एक तरफ बह कर चोरल नदी में मिलता था और दूसरी तरफ वहां से बहकर चंबल नदी में मिलता था। इस बात को उसी समय मैंने उठाया भी था।कि इस पहाड़ी का पानी यहां से बहकर पूरी नर्मदा और चंबल से जमुना और गंगा को हुबली तक दूषित करेगा पर उस समय का क्षेअ अहिरवार क्योंकि मोटे कमीशन के लिए काम कर रहा था। वह मुझसे बार-बार मेरे हर प्रश्न पर चिढ़कर और बदतमीजी से पेश आता रहा। मैंने उसी समय मैंने कह दिया था यह कंपनी जो कि इसका इतिहास बहुत गंदा भ्रष्टाचार और कार्य जालसाजी पूर्ण रहा है। यहां सीमेंट कंक्रीट की लेयर उसके ऊपर बिजली के हीटर से कचरा लेकर जलायेगी नहीं। वरन् केवल गड्ढे खोदकर वहां छोड़ देगी और उसी में कचरा दबाकर रख दिया जाएगा।

इस पर से बरसात के समय पानी बहकर चंबल से गंगा को और चोरल से नर्मदा को गुजरात

तक प्रदूषित करेगा। उसी वक्त यह भी निश्चित हो चुका था कि यूनियन कार्बाइड का कचरा वहां लाकर जलाया जाएगा। जबकि मैं उस समय ही कह चुका था कि वह घातक मिक को जलाया नहीं जाएगा गड्ढा खोदकर दबा दिया जाएगा। चूँकि पत्रकारों की श्रेणी में मुझे अध्ययनशील व कानूनों का पढ़ कर बात व लिखने वाला माना जाता है। इसलिए हर उच्च पद पर पदस्थ अधिकारी मुझ से बचने की कोशिश करता है। मेरे हर कानूनी स्तर के प्रश्नों पर हर पहलू को क्षेत्रीय अधिकारी अहिरवार ने चिढ़कर और बदतमीजी से जवाब दे रहा था।

मेरे पास वीडियो शूटिंग कैमरा होने के साथ में हर तथ्य को रिकॉर्ड कर रहा था। वह मुझे उसी प्रदूषण मंडल के कर्मचारियों ने चमकाने धमकाने की भी पूरी कोशिश की थी। वह कचरा निपटान केंद्र जैसा कि जून 2006 के समय मैंने कहा था गड्ढा खोदकर सारे प्रदेश की बड़ी फैक्ट्रियों उद्योगों का घातक रसायन युक्त कचरा वहां पहुंचाया जाता है। उसके बदले वह काफी मोटा धन वसूल करता है परंतु जैसा कि उस समय कहा गया था उस रामकी कंपनी ने उस 8 करोड़ में भी मात्र जमीन का पैसा चुकाया और बाउंड्री वॉल खींचकर केवल बड़े-बड़े गड्ढे खोद दिए और पूरा पैसा हजम कर लिया गया ।

अब धीरे-धीरे ट्रकों के माध्यम से बहुत 2600मीट्रिक टन यूनियन कार्बाइड की मिक गैस का निक्षेपित रसायन वहां लाकर गड्ढों में दबाया जा रहा है और ऊपर से पॉलीथिन मोटी ब्लैक 3 से 5 मिलीमीटर उस कचरे को दबाकर उस पर मिट्टी डालकर पौधारोपण किया जा रहा है। अर्थात विषैला घातक रसायन आने वाले कल में उस पूरे पीथमपुर के औद्योगिक क्षेत्र को पूर्णता जहरीला बना देगा। वैसे भी वर्तमान में पीथमपुर से 12-15 वर्ग किमी क्षेत्र में अधिकांश ट्यूबवेल जहरीले हो चुके हैं। पूरा प्रदूषण मंडल सब जानता है पर चुपचाप मोटा धन हजम कर के आंख मींचकर बैठा हुआ है। पूर्व में इंदौर में पदस्थ घोर भ्रष्ट, अय्याश और लालची क्षेत्रीय अधिकारी अच्युतानंद मिश्रा इन्हीं सद्गुणों के चलते वर्तमान में मोटा धन खर्च कर पिछले 8-9 बरसों से पूरे मंडल का सचिव बनकर बैठा हुआ है। मोटी कमाई करते हुए, जनता के दुख दर्द और परेशानियों से दूर, पर्यावरण कृषि भूमि, वनभूमि मध्य भारत से निकलने वाली नदियों में प्रदूषित जल बहाते हुए बर्बादी करते हुए चंबल यमुना से गंगा और चोरल से नर्मदा को गुजरात के मुहाने तक बर्बादी में आंख मीच कर भूमिका अदा कर रहा है।

पीथमपुर से प्राप्त कुछ युवाओं की रिपोर्ट के अनुसार आसपास के 12-15 वर्ग किमी के ट्यूबवेल व सतह पर संग्रहित जल के स्त्रोतों को प्रदूषण से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है आजू बाजू के गांव की जनता प्रदूषित वातावरण जल और भूमि के कारण अनेकों बीमारियों की शिकार हो रही है पर जब रक्षक ही भक्षक राक्षस बन नोचने खाने लगे पीथमपुर के नगर पालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अध्यक्ष वहां के विधायक धार का कलेक्टर एसडीएम सब चुपचाप कंपनियों से मोटा धन लेकर हजम कर रहे हैं पर कोई भी जनता की परेशानी सुनने को तैयार नहीं निसंदेह यह मामला अब अंतरराष्ट्रीय बना दिया जाएगा जो हाल उज्जैन जिले की नागदा तहसील में बिरला की रसायन फैक्ट्रियों के कारण नागदा के आसपास की सैकड़ों एकड़ भूमि और चंबल नदी का हुआ है।

वही हाल पीथमपुर में भी हो चुका है। जिसे गूगल अर्थ पर देखा जा सकता है।

केंद्रीय मंत्री नितिन की ट्रांसपेरेंसी की बात बकवास हर वर्ष 5 लाख मरते हैं सड़कों पर

केंद्र की व राज्यों की स्तरहीन बीओटी सड़कों पर लूट का तांडव

सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 4 की पार दर्शिता के अंतर्गत 17 बिंदु की जानकारी भूतल परिवहन मंत्रालय की, और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की साइट पर क्या पूरी उपलब्ध करवा दी। यहां तक की किस योजना में कितना आवंटन किस राज्य को दिया, कौन-कौन से निविदाएं कब निकाली गई उनकी कीमत ठेके की शर्तें, मार्गों की लंबाई, ठेकेदारों के, सलाहकारो के नाम पते, वित्त देने वाली बैंक का नाम उनकी शर्तें, क्या थी कौनसी टोल सड़क कितने किलोमीटर की, टोल की दरें क्या हैं। 15 साल के बाद भी, नहीं क्योंकि पूरे मंत्रालय में घोर भ्रष्टाचार का तांडव किया जा रहा है। सड़को पर टोल के नाम डकैती डालकर भी सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण सड़के नहीं। हर दिन औसतन 2हजार लोग सड़कों पर मरते हैं।

भारत में पिछले 5 वर्षों से भाजपा की सरकार के भूतल परिवहन मंत्री गडकरी यह बताएं वर्तमान में लगभग 2लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कें देश की बी ओ टी टोल टैक्स कर दी गई। जिन पर कार से भी दो से तीन रुपए प्रति किमी वसूली की जा रही है। जो सैद्धांतिक रूप से देश के महंगाई इंडेक्स से जुड़ा हुआ है।

क्या महंगाई का इंडेक्स सन 2014 से 2019 तक आते-आते 4 से 5 गुना हो गया, सड़कों की गुणवत्ता तो दूर 80 किलोमीटर से ज्यादा की गति पर दो -चार पहिया वाहन उछलते कूदने लगते हैं। सुरक्षा मानदंडों का ध्यान नहीं, दुर्घटनाएं ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा अच्छी नहीं।

किसी भी नेशनल या स्टेट हाइवेज सड़क पर निकल जाइए 80-90 किमी की गति से तेज होने पर राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कें भी बेशक लिपीपुती दिखती है। परंतु 80-90 किमी की, और राज्य मार्गों पर 50-60 किमी गति से ऊपर जाते ही वो उछलने कूदने लगती है।

राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कों में

इंदौर से लगी हुई बाईपास देवास महू 45 किमी मांगलिया रिंग रोड पर देवास टोल पर एक तरफ का रु. 85 लंबाई मात्र 25 किमी, इंदौर से मुंबई जो पहले nh3 था। इंदौर से अहमदाबाद जो पहले एनएच 59 था जो अब 47 हो गया। इंदौर से सिरपुर के आगे एयरपोर्ट पीथमपुर रोड के आगे से धार तक 50 किलोमीटर कार की टोल रु.130 एक तरफ की लूट हो रही है। दूसरी और पिछले वर्ष बनारस में गिरा हुआ पुल किसका था। नितिन गडकरी के बेटे सारंग गडकरी का ही था।

अधिकांश टोल वसूली वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम और नंबर बदल दिए गए इसके पीछे लाखों करोड़ का बैंकों का ऋण हजम करने की जालसाजी का हिस्सा हो सकती हैं। सबसे ज्यादा रा. रा. टोल सड़कों पर नितिन या उसकी फर्मों की हैं या साझेदारी में हैं।

सारी टोल सड़कों की डीपीआर चौगुनी से लेकर 10 गुनी कीमतों की, की जाकर 25% हिस्सा भर टोल ठेकेदारों का होता है।

बाकी 75% धन बैंकों से स्वीकृत करवाया जाता है। इसकी गारंटी केंद्र सरकार देती है। यह है भ्रष्टाचार की पारदर्शिता दूसरी तरफ कल रात में मैंने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की साइट को खोल कर प्रति कि मी टोल दरों को जानने का प्रयास किया पर वह काफी प्रयास के बाद में भी नहीं मिली।

दूसरी तरफ संबंधितों से से बात करने पर जिस सड़क की जितनी लागत टोल दरें उसके साथ निर्धारित की जाती हैं। जो डीपीआर का 10 गुना बताएं। जिसमें प्रति किलोमीटर 25 लाख से 10 करोड़ रुपए तक 5 केंद्रीय मंत्रालय जिसमें वन एवं पर्यावरण भूतल परिवहन मंत्रालय वित्त मंत्रालय आदि शामिल है के सचिव और मंत्रियों को चाहिए पड़ता है। यह भी उसी डीपीआर के ऋण में ठेकेदार को बैंकों द्वारा स्वीकृत किया जाकर जनता के सीने पर 15 से 25 साल तक की वसूली के लिए ठोक दिया जाता है।

इस प्रकार से यह लूट का सिलसिला अनवरत चलता रहता है।यदि ठेकेदार जो नेताओं विधायकों सांसदों मंत्रियों के और केंद्र और राज्यों में बैठे भारतीय सेवा प्रताड़ना अधिकारियों के अपने होते हैं लूट कर खा जाने के बाद यदि बैंक का ऋण जमा नहीं होता है तो उसकी भरपाई सरकार को जनता के पैसे से सीधे ही गारंटी के अंतर्गत करनी पड़ेगी। यह है इस टोल का जनता के सीने पर जाल साज डकैत राजनीतिक नेताओं मंत्रियों अधिकारियों और पूंजी पतियों का जनता को लूटने का षड्यंत्र रूपी ठोल हर सड़कों पर से गुजरने का।

बेशक इसकी प्रथा 1999 से सन 2004 के बीच अटल सरकार की विनिवेशीकरण और डकैती की नीति का हिस्सा थी। पहले फर्जी तरीके से 4 से 10 गुना ज्यादा कीमत पर डीपीआर पर सड़कों का बी ओ टी के अंतर्गत निर्माण करवाएं और जनता के वाहन चालकों को 15 से साल तक सरकारी डकैती से लूट के खाएं।

म.प्र. में भाजपा सरकार के 15 साल , शिक्षा जगत का बंटाधार

कानून की परीक्षा में फेल छात्र भी बन गये न्यायाधीश

शिवराज सिंह चौहान के शासनकाल में शिक्षा को एक उच्च स्तरीय व्यवसाय का मॉडल बना दिया है।पहले तो शिक्षा का निजीकरण किया गया। स्कूल,कॉलेज,विश्वविद्यालय और तमाम तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों का उदय हुआ। निजी क्षेत्र के और शासकीय स्तर पर भी । इन सभी कार्यों में भूमि भवन और उपयोग में आने वाले उपकरण और सामग्री क्रय पर खूब जनधन खर्च किया। मगर शिक्षा,शिक्षक ,गुणवत्ता और छात्र के नाम पर सिर्फ व्यवसायिक उपयोग किया। निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक सिर्फ व्यवसाय हुआ। अर्थात प्रदेश में जन्मी कम से कम दो पीढ़ियों का जीवन बर्बाद कर दिया । प्रारम्भिक शिक्षा ऐसी कि कक्षा 10 तक किसी छात्र को अनुत्तीर्ण ही नहीं करना है। 10 बीं और 12 वीं का बोर्ड परीक्षा है उसमें भी अधिकतम किसी भी हाल में उत्तीर्ण ही करना है। कॉलजो का भी ऐसा हाल कि छात्र को सिर्फ पूर्व से निर्धारित निश्चित समय पास करना है और डिग्री हाथ में आ जायेगी। सरकार के सहयोग से इस शिक्षा जगत के कई राजनीतिक महापुरूष प्रगाढ़ विद्वान बन गये तो कई सरकार के दलाल रूपी सहयोग के लिए प्रबन्धक बन गये, तो वहीं अनेको धन बल के दम पर डाक्टर,शिक्षक,इंजीनियर ,अधिवक्ता बन गये । इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं है कि जिन लोगों के पास की कभी दो जून का भोजन और जीवन में आर्थिक स्थिरता भी नहीं थी वे आज कॉलेज और निजी विश्वविद्यालयों के स्वामी बन गये है। इसके सामाजिक दुष्परिणाम भी देखने को मिले है। व्यापम महाघोटाला अभी न्यायालय और जॉच ऐजेन्सी की गोद में बैठा हुआ है। कई नेता,मंत्रियों के पुत्र-पुत्रियां,भॉजे-भॉजियॉ नजदीकी रिश्तेदारों के इस कार्यकाल में भाग्य खुल गये कोई ,प्रशासक बन गया कोई,शासक कोई कॉलेज ,विश्वविद्यालय का स्वामी तो कोई मूक बधिर आम जनता के शरीर से डॉक्टर बनकर लाइला-इलाज का खेल खेल रहा है। तो कोई अदालत में बैठ, मी लॉर्ड बनकर लोगो के जीवन का फैसला कर रहा है। आज हालात यह है कि जिस सरकार का मुखिया बनकर शिवराज सिंह चौहान ने लगभग 13 साल विकास का ढोल बजाया, उस राज्य के किसी भी संस्थान पर खुद को ही भरोसा नहीं है। अर्थात अपना स्वयं का गला भी जॉच कराना है तो चेन्नैई,अपने पुत्र को बकालत की पढ़ाई करानी है तो पूना,और अपने सगे रिश्तेदार या स्वयं के पिताजी भी क्यो न हो मुंम्बई उपचार के लिए भेजना पड़ा है। यह तो एक नमूना मात्र है,गुणवत्ता और विश्वास का। भोपाल स्थित राजीवगॉधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ.मुकेश गुप्ता को भ्रष्टाचार का दोषी मानकर बर्खास्त किया गया था। माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. कुठियाला जो हाल ही में हटाये गये है,के वारे में भ्रष्टाचार के प्रकरण अभी प्रारम्भिक जॉच प्रचलन में ही है। इसी प्रकार जीवाजी राव विश्वविद्यालय ग्वालियर, भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय भोपाल, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इन्दौर,रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर सहित सभी विश्वविद्यालय सरकार की नाक के नीचे षडयन्त्र करते रहे और सरकार मूक बनकर तमाशा देखती रही है। प्रबन्धन बोर्ड एवं संचालन समितियों में अन्य समितियॉ भी राजनीतिक अनुमोदन से नियुक्तियॉ होती है। और राजनेता का कोई चारित्रिक मापदण्ड तय नहीं होता है। मध्यप्रदेश के शिक्षा जगत में। कौन कितना योग्य है कोई मापदण्ड नहीं बचा है। पैसा और समय है तो डिग्री है। डिग्री और राजनीतिक पहुँच है तो रोजगार है,पद है प्रतिष्ठा है और सरकारी सम्मान है। घटना क्रम कुछ इस प्रकार है कि मध्यप्रदेश भोज (मुक्त)विश्वविद्यालय भोपाल में एल.एल.एम.की परीक्षा वर्ष 2011 है हुई,जिसका परिणाम सितम्बर 2011 में घोषित किया गया। इसमें एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में 68 में से 57 विद्यार्थी फेल हो गये ,08 विद्यार्थी विथहेल्ड (नकल के कारण)किये गये तथा मात्र 3 विद्यार्थी ही उत्तीर्ण हो पाये थे। तथा एल.एल.एम. अंतिम वर्ष में 66 परीक्षार्थियों में से 44 फेल,04 विथहेल्ड तथा 17 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हो पाये थे। इनका विधिवत प्रक्रियाअनुसार टेबुलेशन रजिस्टर विश्वविद्यालय की वेब साइट पर भी प्रदर्शित करके परीक्षार्थियों को अंकसूची भी वितरित की गई थी। जिसका उल्लेख मध्यप्रदेश भोज (मुक्त)विश्वविद्यालय की टेबुलेशन रजिस्टर माह सितम्बर 2011 के रिकार्ड में भी मौजूद है।

दिसम्बर 2012 में एल.एल.एम. प्रथम वर्ष के अनुत्तीर्ण एवं विथहेल्ड परीक्षार्थियों को फेल से पास एवं एल.एल.एम. अंतिम वर्ष के अनुत्तीर्ण एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण एवं इनकी उत्तर पुस्तिकाओं में हेरा-फेरी से अंक बढ़ाकर स्वयं अधिकारियों की हैण्ड राइटिंग में फइल एवं काउन्टर फाइल बनाकर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। इस कार्य में कूटरचित टेबुलेशन रजिस्टर एवं फर्जी अंकसूचियॉ बना कर वितरित की गई। जो कि विश्वविद्यालय के टेबुलेशन रिकार्ड में मौजूद है। इस संबंध में एक शिकायत होने पर कार्यवाही के लिए इनकी उत्तर पुस्तिकाऐं तत्समय सुरक्षित रखवाने के आदेश भी हुए थे।

परिनियम 60 के अनुसार पुर्नमूल्यांकन का निर्धारित नियम है कि अधिकतम 2 प्रश्नपत्रों में ही पुर्नमूल्यांकन कराया जा सकता है। इसमें 2 परीक्षक प्रदेश के बाहर के होने चाहिए एवं 10 प्रतिशत से अधिक अंक बढ? पर तीसरे परीक्षक से पुर्नमूल्यांकन कराने के नियम है। यदि यहॉ भी कोई शंका कुशंका संदिग्धता होती है तो चतुर्थ परीक्षक से पुर्नमूल्यांकन कराये जाने के नियम लागू है। परन्तु सितम्बर 2011 में एल.एल.एम के परिणाम घोषित होने के बाद दिसंबर 2011 में कुलपति एवं उनके सहयोगी अधिकारियों द्वारा कुलपति के निवास पर ही उत्तर पुस्तिकाओं में स्वयं की हस्तलिपि में अंको मे हेरा-फेरी की गई और अवैध तरीके से अंक बढ़ाये गये। इसी क्रम में फाइल एवं काउन्टर फाइल तैयार की गई,इसी के आधार पर कूटरचित टेबुलेशन रजिस्टर एवं अंकसूचियॉ बनाने हेतु लखनऊ की रिजल्ट प्रोसेसिंग एजेन्सी को भेजा गया,एवं कूटरचित परीक्षा परिणाम तैयार होकर आने पर इन कूटरचित टेबुलेशन रजिस्टर के आधार पर जारी अवैध अंक सूचियॉ परीक्षार्थियों को वितरित की गई, तथा पूर्व में वितरित अंक सूचियॉ जमा करा ली गई।

यह सभी कूटरचित टेबुलेशन रजिस्टर और अंकसूचियॉ परीक्षा विभाग को दिनांक 29.11.2012 को प्राप्त होने पर कुलपति द्वारा अनुमोदित किया गया,एवं परीक्षा परीक्षा समिति में रखा गया। समिति के निर्णय अनुसार परीक्षर्थियों से आवेदन लेने के उपरान्त बाहरी दो परीक्षकों को उक्त परीक्षा परिणम अवलोकरन कराने का उल्लेख किया गया। जिसको कुलपति ने दिनांक 29/11/2012 को अमान्य कर परीक्षार्थियों को सीधे अंकसूचियॉ वितरित करने के लिखित आदेश दिये । इसके उपरान्त अगले ही दिन दिनांक 30/11/2012 को परीक्षा समिति द्वारा कूटरचित परीक्षा एवं अंक सूचियों को मान्य करते हुए पूर्व घोषित परीक्षा परिणाम सितंबर 2012 एवं इनकी अंकसूचियो को निरस्त करने की अनुशंसा की ,जिसको कुलपति द्वारा अनुमोदित किया गया और परीक्षा नियंत्रक डॉ राजश्री शास्त्री द्वारा एल.एल.एम.प्रभारी शिक्षक को अंकसूचियॉ वितरित करने के लिए सौप दी गई ,जिस पर परीक्षार्थियों से एकत्रित पुर्नमुल्यांकन राशि डॉ. आभा स्वरूप द्वारा विश्वविद्यालय के खाते में जमा कराई गई। यह समस्त तथ्य विश्वविद्यालय की कार्यवाही की नस्ती में मौजूद है। यह कार्यवाही तत्कालीन कुलपति डॅ.एस.के.सिंह कुलसचिव डॉ.आनन्द कामले ,परीक्षा नियंत्रक डॉ.राजश्री शास्त्री,निदेशक आभा स्वरूप एवं डॉ. जी.एस.गौतम द्वारा की गई जोकि रिकार्ड में मौजूद साक्षात सामूहिक कूटरचना और भ्रष्ट आचरण का प्रमाण है।

ऐसा नहीं है कि यह काम कोई समाज सेवा में किया गया है। विधिवत इसमें विधिक सेवा के लोगो ने कहीं सीधे तो कहीं सत्ता के गलियारों में से सिफारिशें कराई और करोडों की राशि का अवैध लेन देन भी किया गया। इसके लिए विधिवत राशि लेनदेन के लिए डॉ.आभा स्वरूप को जिम्मा सौपा गया। इनके माध्यम से ही उत्तर पुस्तिकाओं के पुर्नमूल्यांकन की निर्धारित राशि के जमा कराने का जिम्मा भी इन्हीं के पास था। डॉ.आभा स्वरूप ने उसमें भी हेरा फेरी कर डाली । इस घोटाले को विशेष पुर्नमूल्यांकन का नाम दिया गया। म.प्र. भोज (मुक्त)विश्वविद्यालय में पुर्नमूल्यांकन हेतु प्रति प्रश्नपत्र रू 200/-प्रति परीक्षार्थी निर्धारित था। किन्तु 160 परीक्षार्थियों के 5 प्रश्नपत्रों का पुर्नमूल्यांकन कराने की फीस लगभग रू.200000/-(दो लाख) रूपये डॉ. आभा स्वरूप एवं इनके सहयोगियों द्वारा परीक्षार्थियों से नगद राशि एकत्रित कर विश्वविद्यालय के खाते में जमा नहीं कराई इस राशि को अपने पास ही रखे रहीं। और निजी उपयोग में लेती रहीं। यह वह राशि है जो फेल परीक्षार्थियों से पास करने के नाम पर अवैध राशि से अलग बसूल की गई थी। अर्थात इनकी सह भागिता विश्वविद्यालय के कुलपति,की खासखास अतिविश्वसनीय और निजी मुनीम की भूमिका में सह-भागीदार रही है।

इस विशेष उच्च स्तरीय घोटाले की शिकायत मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो कि यहॉ के कुलाधिपति भी होते है के द्वारा नियुक्त प्रबंध बोर्ड के सदस्य श्री एच.आर.यादव द्वारा दिनांक 02/03/2013, दिनांक 13/05/2013,दिनांक 28/05/2013,दिनांक 30/08/2013,एवं दिनांक 09/06/2013,को निरन्तर की गई। जिसके तारतम्य में प्रबंध बोर्ड की 58वीं बैठक में जॉच समिति बनाने के आदेश भी दिये गये। इसके लिए तत्कालीन कुलपति डॉ. तारिक जफर द्वारा दिनांक 27/06/2014, में जॉच समिति गठन के लिए आदेश भी किये है,जोकि म.प्र.भोज मुक्त विश्वविद्यालय के आदेश क्र.373 दिनांक 27/06/2014 द्वारा आदेशित हुई है। गठित समिति ने उक्त प्रकरण कुलाधिपति अर्थात महामहिम राज्यपाल को भेजने की अनुशंसा कर दी,चूँकि इस वृहद स्वरूप के फर्जीबाड़े के मुखिया तत्कालीन कुलपति के विरूद्ध केवल कुलाधिपति ही जॉच कर सकते है और निर्णय ले सकते है। सत्यता यह है कि महामहिम का पद सत्तापक्ष की राजनीति और राज्य सरकार का केन्द्रीय स्तम्भ है और इस पद को धारण करने के लिए कोई भी शैक्षणिक मापदण्ड भी नहीं है। अर्थात स्वविवेक पर निर्भर बिना किसी संबैधानिक हस्तक्षेप के सब कुछ एकाधिकार में संरक्षित है।

इस प्रकार के तथ्यों के अवलोकन और विश्वविद्यालय में मौजूद अभिलेखों के आधार कहा जा सकता है कि वर्ष 2011 में कूटरचित टेबुलेशन रजिस्टर एवं अवैध अंक सूचियॉ बनाकर अवैध परीक्षा परिणाम को वास्तविक अभिलेख निरूपित करके परीक्षार्थियों को षडयन्त्रपूर्वक निजी स्वार्थो की पूर्ति और उच्च स्तरीय विधिक सेवा में अपनी अवैध पहुँच बनाने की नीयत से संविधान में निहित विश्वास और व्यवस्था को खण्डित करने का घृणित कृत्य किया गया है। विशेष पुर्नमूल्यांकन के नाम पर करोड़ो की राशि का लेनदेन किया गया। दो विषय से अधिक विषयों में पुर्नमूल्यांकन का कोई प्रावधान भी नहीं है। न ही ऐसा कोई कानून है। मगर लगभग सभी विषयों में विशेषपुर्नमूल्यांकन के नाम पर अंक बढ़ाने की कूटरचना की गई। कुलपति ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उत्तर पुस्तिकाओं ,फाइल,एवं काउन्टर फाइल में अवैध रूप से कूटरचना कर अंक बढ़ाये गये । कूटरचित अभिलेखों के आधार पर ही परीक्षा ऐजेंन्सी से कूटरचित टेबुलेशन रजिस्टर एवं अंकसूचियॉ बनवाई गई तथा इन अंकसूचियों को वितरित करने के पूर्व परीक्षार्थियों से अण्डरटेकिंग लेकर,फर्जीवाड़े के जनसामान्य में प्रदर्शन होने के भय से पुरानी फेल वाली अंक सूचियॉ भी जमा कराई गई एवं पुर्नमूल्यांकन फीस एकत्रित की गई। और नई पुनःनिर्मित कूटरचित अंक सूचियों को असली सिद्ध करने की नीयत के साथ विधिवत वितरण करने के आदेश भी जारी किये गये । जिनका लाभ आज सर्वत्र देखा जा सकता है। इसमें लाभार्थी कोई सामान्य लोग नहीं है बल्कि लोगों के जीने और मरने का आदेश देने वाले अधिकांश न्यायाधीश है। तो कोई शासकीय अधिवक्ता है तो कोई कानून का पैरोकार ।

यह भाजपा का विकास मंत्र है
मठाधीश है,भ्रष्टकुलपति,कुलाधिपति।
विधान खण्ड-खण्ड करने बना
रहे धनपिशाच और न्यायाधिपति ।।

हर वर्ष रु 10 हजार करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार, शिवराज और राजोरा के भ्रष्टाचारी प्रिय पात्र थे

म प्र की कृषि की बर्बादी और लूटपाट का जिम्मेदार राजोरा

पहले भ्रष्ट अधिकारियों को लूट और भ्रष्टाचार के अवसर देना, फिर अधिकारियों को फंसाना, फिर कारण बताओ नोटिस देना, निलंबित करना, मोटा धन बटोर कर मनचाही पदस्थापना करना इस जालसाज भारतीय प्रताड़ना सेवा के अधिकारी के पुराने शगल थे। अधिकांश अधिकारी अनेकों जांचों में लिप्त होने के उपरांत ही पदोन्नत होकर शान से कार्य कर रहे हैं। सन् 2003से 18 तक कृषि में डेढ़ लाख करोड़ का भ्रष्टाचार किया गया।जिसकी कमलनाथ सरकार को जांच करनी चाहिए। बेशक इसीलिए शिवराज ने मोटे हिस्से के चलते उसे इतना महत्वपूर्ण पद पर बैठा रखा था! भ्रष्टाचार छुपाने कृषि कर्मण अवार्ड पैसे देकर इसीलिए खरीदे जाते थे।भावांतर मैं भी लगभग 5हजार करोड से ज्यादा का भ्रष्टाचार किया गया।

मप्र कृषि विभाग में पूर्व का प्रधान सचिव राजेश राजौरा ने 16-17 में रु 25-26 रु किलो की ढेंचा गोबर की खाद खरीदी का सौदा रु130/- प्रति किलो लगभग 50 हजार टन खरीदा, और उस स्तर हीन जैविक खाद को 33%, अनुसूचित जाति को 50% और आदिवासियों को 66% अनुदान पर माल बेचने के लिए, मृदा परीक्षण किट जो रु 5000 की थी 1 लाख 5 हजार में लगभग 40000 किट की खरीदी, उपयोग किए जाने वाला रसायन भी 10 गुना कीमत पर खरीद की जाकर प्रदेश के 51 जिलों के उपसंचालकों को बांटने के लिए थोप दी गई। पाठकों को बता दें की जैविक खाद के नाम पर, सरकारी तंत्र जिसमें जिलों के उपसंचालक जो भारी भ्रष्ट होते हैं उन्हीं को बैठाया जाता है मोटा धन लेकर ऐसे स्तरहीन, अनाजों, दलहनों, तिलहनों बीज, जैविक, रासायनिक खाद कीटनाशक खुले में जालसाज उत्पादकों व विक्रेताओं को, मोटा धन लेकर लाइसेंस जारी कर देते हैं। जो पूरे देश- प्रदेश के किसानों को ऊंची कीमत पर बेचकर किसानों को, आर्थिक, सामाजिक व मानसिक रूप से हर तरह से बर्बाद करते हैं। किसान अच्छी फसलों के लिए, साहूकारों बैंकों और समितियों से ऋण लेकर ऊंची कीमतों पर खाद बीज कीटनाशक खरीदकर पूरी मेहनत कर अच्छी फसल लेने का प्रयास करता है। परंतु जब फसल बिगड़ती है और मनचाहा उत्पादन नहीं मिलता तो कर्ज भी, पूरा व समय पर न चुका पाने के कारण उसे आर्थिक सामाजिक और मानसिक रूप से आघात मिलता है।उससे वह अंत में आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता है देश में प्रदेश में हर वर्ष लाखों किसानों की आत्महत्या के पीछे इन धूर्त, मक्कार, घोर भ्रष्ट, गिद्धों का मकड़जाल ही है।

केंद्र सरकार की खेत का पानी खेत में बलराम तालाब जैसी योजनाओं में खरगोन में उपसंचालक सिसोदिया के रहते हुए उसके खास चेले विजय चौरसिया जो भूमि संरक्षण अधिकारी था।वर्तमान में सिसोदिया इंदौर संभाग का सेक्स संयुक्त संचालक है विजय चौरसिया नीचे इंदौर का उपसंचालक अभी भी गुरु चेले भ्रष्टाचार का तांडव मचाए हुए हैं और एक दूसरे को बचाते हैं हरामखोर। खरगोन में इन दोनों ने मिलकर सैकड़ों तालाब कागज पर बनाकर किसानों के नाम से खाता खुलवा कर करोड़ों का अनुदान हजम कर लिया था जांच लंबित है परंतु मोटा धन देने के कारण दोनों पदोन्नत होकर इंदौर में ही स्थापित हो गए। इंदौर की पदस्थापना में भारी शिकायतें के चलते शिवराज ने हीं निलंबित कर मुरैना भेज दिया था परंतु इसी भ्रष्ट प्रधान सचिव राजोरा ने मोटा धन लेकर उसे पुनः इंदौर में स्थापित कर दिया। वैसे राजोरा के पर लोकायुक्त के अनेकों भ्रष्टाचार की लंबित जांचों में पैसा देकर बच के निकला इसकी करोड़ों की संपत्ति इसके भाइयों पिताजी और साले-साली, सास-ससुर के नाम से, भोपाल, इंदौर नीमच व आस-पास के गांवों में होने की जानकारी लोकायुक्त को भी है। जहां चाहे पूर्व में एसडीएम कलेक्टर बंद कर पदस्थ रहा वहां सब जगह पर इसने काफी संपत्तियां एकत्रित कर रखी है! नाथ सरकार और वर्तमान प्रधान सचिव को चाहिए पिछले 15 सालों में किन-किन भ्रष्ट अधिकारियों पर हजारों तालाब चोरी, हजारों करोड़ के बीज, खाद, कीटनाशकों, की खरीद आवंटन आदि में, सूक्ष्म सिंचाई योजना हजारों करोड की भारी भ्रष्टाचार की विभागीय जांचें शिकायतों पर शुरू हुई, सैकड़ों अधिकारियों को कारण बताओ पत्र जारी करके, निलंबन भी किया गया। परंतु लाखों में लेन देन कर आरोप पत्र जारी नहीं किए या जांच के नाम पर धन के समायोजन होते ही ना केवल प्रकरण बंद कर दिए गए। अब जब सरकार बदल गई है किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा गर्म है आखिर प्रदेश के 80 लाख से ज्यादा किसानों को कर्जदार बनाने वाले घोर भ्रष्ट जालसाज पूर्व मुमं शिवराज, प्रस राजोरा, पूर्व संचालक मीणा, 15 से ज्यादा संयुक्त संचालको, सौ से ज्यादा उपसंचालको, 200 से ज्यादा सहायक संचालकों को, सबसे ज्यादा वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी आदि को इनके भ्रष्टाचार की सजा कब मिलेगी?

साप्ताहिक समय माया

भाजपा के पंजीयन विभाग में हुए घोटालों की जांच होनी चाहिए

बरसों से बैठे जालसाज उप पंजीयकों के कब होंगे स्थानांतरण

पूर्व में कानून की डिग्री धारी वकील ही पंजीयन कार्य करते थे। परंतु ई पंजीयन इसकी न्यूनतम योग्यता 12वीं क्लास है। परन्तु आठवीं दसवीं पास कंप्यूटर ऑपरेटरों को ई पंजीयन का कार्य मोटी वसूली कर अधिकृत कर दिया। इसकी सूक्ष्मता से जांच होने पर, ई पंजीयन में स्टांप ड्यूटी की चोरी और दूसरी अन्य जालसाजीयां भी सामने आएंगी। दूसरी तरफ अधिकतम एक करोड़ की लागत का ई पंजीयन सॉफ्टवेयर का भुगतान विप्रो कंपनी को साढे 5सौ करोड़ हुआ इसकी भी जांच होनी चाहिए।

मध्यप्रदेश में शिवराज की 15 वर्ष की सरकार में हर कदम हजारों करोड के बड़े-बड़े घोटाले किए गए, जिसमें हजारों करोड़ का बड़ा घोटाला अधिकांश विभागों के विभागीय कार्य के लिए बनाए गए 25-50 लाख के सॉफ्टवेयर को सैकड़ों करोड़ में बनवाया गया। जिसमें एक विभाग पंजीयन भी था। जहां सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर जानकारी देने की तो दूर पत्रों का जवाब भी नहीं दिया जाता राजधानी के मुख्यालय से लेकर जिलों के मुख्यालयों तक। पंजीयन विभाग में हजारों करोड़ के एक तरफ मोटे कमीशन पर गैर न्यायिक मुद्रांक छपवा लिए गए। तो दूसरी तरफ विप्रो कंपनी को सैकड़ों करोड़ में सन 2010-11में जो साफ्टवेयर बनाने का ठेका दिया गया वह पूर्णता कार्यशील ना होने और अनेकों परेशानियों के उपरांत भी उसका भुगतान कर दिया गया। शायद 90% कमीशन पर, इ स्टंपिंग मे भी खूब भाई भतीजा वाद हुआ। अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने चारों और खास लोगों को इ स्टंपिंग का कार्य दिलवा दिया। इस कार्य में यह था की ई स्टांप की बिक्री और पंजीयन से पूर्व हर हर जारी करने वाले विक्रेता को अपने बैंक खाते में बैलेंस रखना पड़ेगा। कई बार तो यह हुआ कि ई स्टांप बेंचे किसी ने और पैसा किसी दूसरे के खाते से कटा।इसकी अगर बारीकी से जांच की जाए तो यहां पर भी सैकड़ों करोड़ के घोटाले पूरे मध्यप्रदेश में पकड़ में आएंगे। पर कोई भी इसकी जांच अपने गिरेबान फंसाने के लिए नहीं करता। कमलनाथ सरकार को चाहिए कि वह पुनः स्टांप की बिक्री को भी शुरू करवाएं और स्टांप से भी पारंपरिक तरीके से जो चाहे उसकी रजिस्ट्री की जानी चाहिए क्योंकि अभी जो पंजीयन में पेपर उपयोग किया जा रहा है। ज्यादा भरोसेमंद व टिकाऊ नहीं। सरकार के पास जो हजारों करोड़ के 500, 1000, 2000, 5000, 10000 के मुद्रांक छपे हुए पड़े हैं। आखिर उनका क्या होगा? इसलिए आवश्यक है, की स्थाई संपत्तियों की खरीद-बिक्री में, जो भी क्रेता विक्रेता पारंपरिक तरीके के मुद्राओं का उपयोग करना चाहे, संपत्तियों की खरीद बिक्री के साथ, सभी कार्य विभागों में, वित्तीय संस्थानों, बीमा व्यवसाय में होने वाले ठहराव अनुबंधों में लगने वाली मुद्रांक शुल्क आदि के लिए भी मुद्रित मुद्रांकों की आवश्यकता होती है। उन्हें इच्छा अनुसार छूट होनी चाहिए।

कार्य विभागों, वित्तीय, बीमा संस्थानों आदि में ठहराव पत्रों में लगने वाली 0.5% स्टैंप ड्यूटी में भी भारी घोटाले किए जा रहे हैं। मुद्रांक शुल्क जो कि कुल कार्य की राशि का 0.5% होना चाहिए के स्थान पर धरोहर राशि का 0.5% ई-स्टंपिंग से भुगतान कर रहे हैं। चूंकि कुल राशि का कागज पर उल्लेख मुद्रित होता है इसलिए वह आसानी से समझ नहीं आता। जबकि विभिन्न राशि के मुद्रांक अलग से दिखते थे। जिससे चोरी की संभावना नहीं रहती थी। पिछले 10 वर्षों में सभी शासकीय कार्य विभागों वित्तीय, बीमा संस्थानों में इसकी जांच करवाई जाए अरबों रुपए की मुद्रांक शुल्क की चोरी सामने आ सकती है।

सरकार को धन तो दोनों तरफ ही मिलेगा और मिल रहा था। वैसे इंदौर के साथ पूरे प्रदेश के सभी पंजीयन कार्यालय में बैठे हुए अधिकांश कर्मचारी और अधिकारी में बैठे पंजीयन विभाग में हर कार्य के लिए निर्धारित शुल्क से ज्यादा मोटी वसूली करते हैं। और भारी कमाई कर रहे हैं। इसके ऊपर भी अचानक छापे मारकर जांच व नियंत्रण किया जाना चाहिए।वर्तमान में भी अब जबकि सारे स्थाई संपत्तियों की देखरेख गूगल अर्थ और उपग्रह प्रणाली से जांच की जाती है इसके मकानों का प्लाटो में, सिंचित कृषि भूमि का, असिंचित व बंजर भूमि में धड़ल्ले से मोटी लेनदेन के दम पर खुलकर रजिस्ट्री आंकी जा रही है। वैसे तो पंजीयन विभाग अपनी मोटी लूट और भ्रष्टाचार के लिए शुरू से ही कुख्यात रहा है और वर्तमान में इतनी तकनीकी सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध है जहां से सरकार के अनेकों विभाग जिसमें सभी कार्य विभाग,यथा लोक निर्माण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी ग्रामीण यांत्रिकी जल संसाधन तक पिछले 5 सालों से बड़ी-बड़ी योजनाएं परियोजनाएं तक एक 1 इंच का लेखा-जोखा नाप आदि तक उपग्रह व गूगल मैप से तैयार करते हैं। तो फिर यह पंजीयन विभाग ही क्यों लूट के लिए अपनी मर्जी से दलालों के माध्यम से मोटी कमाई कर पंजीयन में भारी जालसाजिया और भ्रष्टाचार कैसे कर रहा है।

जो की कलेक्टर की नाक के नीचे वर्षों से उपरांत भी पकड़ा क्यों नहीं जा रहा और भू माफिया, कॉलोनी, खनन माफिया, पटवारी, तहसीलदार, सहायक, उप, जिलाधीश के साथ सहायक, उप, जिला, व वरिष्ठ पंजीयक सब मोटी कमाई कर के नीचे सब ऊपर तक बांटने के कारण सभी राजस्व अधिकारियों कर्मचारियों का, जिसमें पटवारी, तहसीलदार, सहायक, उप वह जिलाधिकारी, निगमों पालिकाओं जनपद पंचायतों और ग्राम पंचायतों आदि का भी इन को पूर्ण संरक्षण प्राप्त होता है। क्योंकि सभी की हिस्सेदारी होती है।

जिला कोषालय में हर अधिकारी कर्मचारियों को चाहिए हर दाम का दाम

वेतन बिलों में भी चाहिए पास करने की वसूली

जिला कोषालयों में, हर देयक के भुगतान के लिए पहले कर्मचारी अधिकारियों को भुगतान करना पड़ता है। अभी तक कई विभागों में हजारों कर्मचारियों का सातवें वेतनमान के लंबित भुगतान नहीं हुए, पेंशनर्स को सालों चक्कर कटवाए जाते हैं। मोटी वसूली के लिए। सूचना के अधिकार का पत्र देखकर आधे घंटे तक देवास कोषालय में यहां से वहां चक्कर कटवा कर परेशान किया गया। फिर महिला कोषालय अधिकारी के पास लेकर उनको भी बताया की आवेदन पीछे संलग्न किया गया है। उसने समझने की अपेक्षा उल्टे धमकाया और कहा आप किस से बात कर रहे हैं मैं फर्स्ट क्लास ऑफिसर हूं।

मध्य प्रदेश के अधिकांश जिला कोषालयो में चारों तरफ घोर भ्रष्टाचार है। सभी सरकारी कार्यालयों का वेतन भत्तों से लेकर सभी भुगतान संबंधी कार्य जिला कोषालयों के माध्यम से ऑनलाइन ही होता है।सभी शासकीय कार्यालयों के वेतन भत्तों के, सभी कार्य विभागों के जिसमें स्वास्थ्य, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जल संसाधन, पंचायत बा ग्रामीण विकास, ग्रामीण यांत्रिकी, वन, कृषि, उद्यानिकी, महिला बाल विकास, पुलिस, राजस्व, आदि जैसी 50 से ज्यादा शासकीय विभागों के बिलों के भुगतान हेतु प्रस्तुत करना पड़ता है। यदि वहां कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों को बिना भेंट पूजा के कोई भी भुगतान कार्य संभव नहीं। यदि भेंट पूजा नहीं की गई तो अधिकांश बिल किसी न किसी कारण लगाकर लटका व लौटा दिए जाते हैं चाहे फिर वेतन भत्तों के भुगतान के हो। पेंशन के हो। स्वाभाविक है कि वहां के कर्मचारी व अधिकारियों में बत्तमीजी और घमंड होना ही है।जैसा कि सभी शासकीय विभागों से प्राप्त कर्मचारियों अधिकारियों की शिकायतें लगातार पिछले कई सालों से मिल रही है। यही कारण था की अधिकांश भुगतान कार्य ऑनलाइन किया गया परंतु विलो की जांच और सत्यापन के नाम पर अभी भी भ्रष्टाचार चल रहा है। दूसरी तरफ इंदौर के जिला कोषालय में बैठे घोर धूर्त जिला कोषालय अधिकारी द्वारा, बिना सेवा शुल्क के 200 से ज्यादा मुद्रांक विक्रेताओं को 10, 50 और 100 के मुद्रांक देने में भारी परेशान किया जा रहा है। एक बार सप्ताह में रु. 10000 का चालान ही स्वीकार किया जाता है। जबकि ऐसा कोई भी बंधन कारी कानून नहीं है कि मुद्रांक विक्रेता से सप्ताह में केबल एक चालान रु 10000 से ज्यादा नहीं लिया जाएगा। और मुद्रांक भी उसे दो-तीन सप्ताह बाद किए जाते हैं। जबकि सेवा चाकरी करने वाले मुद्रांक विक्रेताओं को 1 सप्ताह में चार से पांच चालान स्वीकार कर उसे उसी सप्ताह माल दे दिया जाता है। बेशक यह हाल पूरे मध्य प्रदेश के 51 जिलों के कोषालय अधिकारियों का है।यही कारण है की मुद्रांक विक्रेता रु 10 का मुद्रांक 15 में, 50 का 60/-, सौ का 120 में, बेचने के लिए मजबूर है उनका कहना है कि आखिर दो पर्सेंट कमीशन पर सर सारे दिन बैठकर हम क्या खाएंगे और कमाएंगे जबकि हमें को सारे अधिकारी को भी रुपए हजार से दो हजार देना पड़ता है हर महीने। इन भ्रष्ट व्यवस्थाओं पर नई सरकार को लगाम लगाई जानी चाहिए।

वन भूमि पर जल संसाधन विभाग को विकसित करना चाहिए तालाब और बांध

आवश्यकता है, हर कदम पर पानी की हर बूंद को वनों में भी सहेजा जाए, ताकि वनों में हरियाली, सभी प्रकार के वृक्षों के वनों के विकास के साथ वन्य पशु पक्षियों को भी पर्याप्त जल से जीवन मिल सके

भारत में पर्णपाती और बारहमासी जंगलों का प्राकृतिक भरपूर वर्षा के अभाव के साथ मानव की दानवीय प्रकृति और बढ़ती आबादी ने एक तरफ वन भूमि पर बढ़ता अतिक्रमण, कृषि कार्य, औद्योगिकरण, कॉलोनाइजेशन आदि ने भरपूर विनाश किया है। उसका दुष्प्रभाव ना केबल प्रदेश देश वरन पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहा है। विश्व वन्य जीवन संघ जो कि वैश्विक स्तर पर वन्य प्राणियों कल्याण विकास, पुनर्वास आदि के कार्यों को पिछले 80 वर्षों से ज्यादा समय से संपन्न कर रही है। के वास्तविक अनुमानों के अनुसार प्रतिवर्ष से 300 से ज्यादा वन्य प्राणियों की प्रजातियां खत्म होती जा रही है। जिस के मूल कारणों में बढ़ती हुई मानवीय आबादी के साथ मानव की घोर लालची प्रवृत्ति का होना भी है। यथार्थ में विकसित देशों में औद्योगिक विकास, आधुनिकता के नाम पर, वन भूमि पर लगे प्राकृतिक वनों का विनाश करने, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई कर, वहां के प्राकृतिक जल स्रोतो को समाप्त करने पहाड़ों की कटाई कर, कृषि कार्य करने, सड़कें बनाने, उद्योगों की स्थापना फिर अतिक्रमण करके वहां पर मानव आबादी के बसाने, जैविक ईंधन पेट्रोल डीजल की भारी खपत के कारण पूरे विश्व में, बढ़ता हुआ कार्बन डाइ, मोनो ऑक्साइड का स्तर, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का, जिस में कोका कोला, वॉलमार्ट, मैदानी धरती से लेकर हिमालय की ऊंची पर्वत श्रंखलाओं से 12 से 15 किलोमीटर गहरे समुद्र की तलहटी तक में छाई हुई पॉलिथीन की थैलियां शीशियां व अन्य सामग्री से नष्ट होते, जल स्रोतों, नदी नालों के प्राकृतिक बहाव के मार्गों को अवरुध्द करते हुए, बिगड़ते पर्यावरण के कारण वर्तमान में वर्षा का स्तर चारों तरफ पूरे विश्व में गिरा है। और धरा पर घटती हरियाली के कारण प्रकृति का हर तरह से विनाश हुआ है। यह तथ्य सभी सरकारे भली-भांति जानती है। परंतु बहुराष्ट्रीय व बड़े पूजीपतियों की राष्ट्रीय कंपनियों से, सभी मंत्रालयों के प्रधान सचिवों, सचिवों, अधिकारियों और प्रधानमंत्री, मंत्रियों, नेताओं को मोटा कमीशन मिलने और दोस्ती निभाने के कारण कोई भी माई का लाल अपनी मोटी कमाई छोड़ने को तैयार नहीं इसलिए पॉलिथिन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के नाम पर केवल छोटे व्यापारियों उद्योगों, ठेले वालों सब्जी वालों पर कार्वाई कर नगर निगम पालिका ओं से लेकर प्रदूषण मंडल तक कारवाही कर इतिश्री कर ली जाती है। परंतु अपने बहुराष्ट्रीय कंपनियों, राष्ट्रीय कंपनियों जिसमें के बापों की तरफ की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा जाता। ठीक है सरकार में बैठे मंत्री, संत्री अपना मोटा कमीशन खाए परंतु वर्तमान और आने वाले भविष्य के लिए, वनों की भूमि पर नमी बनाए रखने, वृक्षों और हरियाली के साथ वन्यजीवों की रक्षा उनके विकास व जीवन यापन के लिए पर्याप्त जल के लिए व्यवस्थाएं अवश्य करते रहे, इसके लिए आवश्यक है, की भारत सरकार अपने स्तर पर वन व पर्यावरण मंत्रालय के साथ, जल संसाधन मंत्रालय आपस में समन्वय कर 25 हेक्टेयर से ज्यादा के तालाबों और बांधों के माध्यम से नहरें बनाकर पर्याप्त जल की आपूर्ति वन के कोने कोने में कर वर्षा जल का वनों के विकास की व्यवस्था में सदुपयोग अवश्य करें। जिससे जलाभाव में वनों की हरियाली के साथ, अन्य अभी वन्य प्राणियों की अकाल मृत्यु ना हो। क्योंकि प्रकृति में हर वानस्पतिक वृक्षों, झाड़ियों, से लेकर जंगली घास, लघु पौधों, के साथ नमी युक्त जमीन में विकसित होने वाले केंचुए से लेकर अन्य सभी छोटे से छोटे कीड़े- मकोड़े, कीट-पतंगों से लेकर बड़े पशु पक्षियों आदि तक का भारी महत्व आवश्यकता होती है। शास्त्रों व पुराणों के अनुसार, ' जीवो, जीवस्य, जीवनाम'। वनस्पतियों का जीवन, जीवो से, जीवों का जीवन वनस्पतियों पर निर्भर होता है। एक दूजे के बिना जीवन संभव नहीं। परंतु मनुष्य की आने वाली पीढ़ियों के सुखद भविष्य के लिए, सभी वनस्पतियों सभी जीवो का, न केवल जीवन संरक्षित करना, वरन उनके आने वाली पीढ़ियों की वंश वृद्धि सतत होती रहे! इसका भी ध्यान रखना अति आवश्यक है। निसंदेह ऐसे सभी कार्यों में, स्कूली बच्चों से लेकर जनता के सभी वर्गों का विशेषकर ग्रामीणों का सहयोग लिया जाना भी आवश्यक है ताकि सभी के मन में प्रकृति के विनाश को छोड़, प्रकृति के विकास की इच्छा और मानसिकता जागृत हो।

युवा पीढ़ी को मानसिक रुप से उलझाये रखने, सत्ताधीश व पूंजीपति धूर्तों जालसाजों की चाल

देश में क्रिकेट बना रहा युवा पीढ़ी को निकम्मा, आलसी, बढ़ा रहा सटोरिये

दुनिया के बड़े-बड़े आपराधिक प्रवृत्ति के दाऊद जैसे आतंकवादी गिरोह के सटोरियों जिनका जाल पूरी दुनिया के जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दुबई, जिंबाब्वे, साउथ अफ्रीका आदि देशों में फैला हुआ है।

बेशक दुनिया के अग्रणीस देश अमेरिका, जर्मनी, जापान, रूस, चीन जैसे देश क्रिकेट की बीमारी से बहुत दूर है। इसके विपरीत वे सब ओलंपिक खेलों में सबसे ज्यादा मेडल ले जाते हैं।

वैसे भी भारत के क्रिकेट के 11 खिलाड़ी देश के 55 करोड लोगों जिसमें 30 करोड़ युवा हैं, को बर्बाद कर रहे हैं। सटोरियों जिसमें भाजपा और कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं की कठपुतली ये 11 क्रिकेट खिलाड़ी देश के लिए नहीं बल्कि बड़े सटोरियों की कमाई के लिए खेलते हैं। देश में एक अनुमान के अनुसार लगभग दो लाख करोड़ रुपए का सट्टा भारत पाकिस्तान मैच के लिये लगाया गया था। पाकिस्तान के हारने के बाद में भी बड़ा हिस्सा लगभग रू 10 से12 हजार करोड़ पाकिस्तान को ही गया। जिसका मोटा हिस्सा पाकिस्तान की दाऊद गैंग के माध्यम से आई एस आई और आतंकवादियों को जाता है।

यह भारत सरकार जानती है परंतु क्रिकेट मैच बंद नहीं करती क्योंकि उसके पास देने के लिए युवा लोगों को रोजगार नहीं है।

वैसे सच तो यह है कि रोजगार देने के लिए सभी शासकीय विभागो पिछले 30 वर्षों से भर्ती नही हुई हैं। परंतु पूंजीपति मित्रों के इशारे पर सस्ते श्रमिकों के लिए सरकारी विभागों दो करोड़ भर्ती ही नहीं की जा रही और उनका निजी करण किया जा रहा है। ताकि उनको मोटा लाभ हर क्षेत्र से प्राप्त होता रहे।

दूसरी तरफ वह चुपचाप लूट और देश को बर्बाद करते हुए पूंजी पतियों के और विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों इसमें चीन अमेरिका और यूरोप की कंपनियां है के हाथ पूरे देश के प्राकृतिक व मानव निर्मित संसाधनों को बेंच व गिरवी कर रहे हैं। इसलिये वो भेड़ियों के झुंड नहीं चाहते कि देश की आबादी का 60% हिस्सा क्रिकेट के बुखार से बाहर आए। और सच्चाई को समझ कर इनके खिलाफ बगावत न कर दे।

क्रिकेट के जुनून और बुखार का यह सच हमारे देश के लोग और हमारी देश की युवा पीढ़ी कब समझेगी और कब जागेगी?

आखिर क्या मिलता है?

वह 11 खिलाड़ी अपनी हजारों करोड़ की कमाई के लिए 8 से 10-12 घंटे मैदान पर देश के 55-60 करोड़ लोगों के एक ही दिन में मानव जीवन के बिना श्रम किए साढ़े 500 से 600 करोड़ घंटे बर्बाद कर देते हैं।

आंखो को टीवी पर चिपकाये मस्तिष्क को पंगु बनाकर, तन-मन, मस्तिष्क को अनावश्यक तनाव देते हुये शरीर को आलसी और बीमारियों का घर बना देते हैं।

दूसरी तरफ

यही कारण है कि हम चीन से मिट्टी की मूर्तियों से लेकर बड़े-बड़े सामान इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स से लेकर साधारण सी बिजली की झालरें, मिट्टी की मूर्तियां, फटाके, पिचकारिया, राखियां जो हमारे देश के हिंदू धर्म के त्योहारों के बहाने जीवन के आधारभूत उद्योग धंधे थे इन से 30% आबादी को रोजगार मिलता था। खत्म करके उनसे आयात करते हैं।

भेड़ियों के झुंड को 25% कमीशन के बदले पूरा देश गुलाम करने और बेंच देने से कोई हिचक और गुरेज नहीं है।

फिर जब इससे भी दिल नहीं भरता तो तो अपने पूंजीपति मित्रों के लिए उनकी मोटी कमाई और व्यवसाय को बढ़ाने देश पर नोटबंदी ला दी जाती है और 4 महीने पूरे देश को चौराहे पर खड़ा कर बंद कर दिया जाता है।

जब उससे भी दिल नहीं भरता है तो देश के 30 करोड़ लोगों से उनके छोटे-मोटे व्यवसाय धंधा को छीनने बर्बाद करने उन्हें जीएसटी के विदेशी कर संग्रहण नीति के चक्कर में उलझा कर डराया धमकाया जाता है गिरफ्तारी की जाती है और व्यवसाय बंद करने के लिए विवश कर दिया जाता है शायद भेड़ियों का झुंड अमर फल खाकर इस धरती पर पैदा हुआ है जिसे पूरे देश दुनिया का धन चाहिए चाहे वह क्रिकेट के सट्टे के माध्यम से आए देश को बेच कर गिरवी करके आए।

वह जानते हैं कि इससे भयंकर बेरोजगारी फैलेगी। इसके लिए उन्होंने रु. 75000/- साल देने की व्यवस्था, देश की कार्यशील आबादी को नकारा निकम्मा और नामर्द बनाने के लिए अपने चुनावी घोषणा पत्र में कर दी है।

संघ के अधिकारी झूठे यात्रा, होटलों, खेल सामग्री क्रय बिलों से करोड़ों रुपए हजम करते हैं हर वर्ष

प्रदेश में जल संसाधन नर्मदा घाटी के खेल संघों को करो भंग

इंदौर का आशिक अली, होशंगाबाद का वसारत खान के पिछले 10 वर्षों के खेल सामग्री की खरीदी, होटलों, टेटो, खेल मैदानों के किराये के साथ इन दोनों जालसाज हरामखोर खिलाड़ियों ने हर साल लाखों रुपए की यात्रा बिलों का भुगतान अपने विभागों से अधिकारियों के साथ मिलकर फर्जी तरीके से वसूला। जिसकी तत्काल जांच की जानी चाहिए और इनकी जांच कर लोकायुक्त के द्वारा गिरफ्तारी करवा शीघ्र इनकी संपत्तियों को जब्त किया जाना चाहिए।

मध्य प्रदेश के पूरे नर्मदा घाटी भ्रष्टाचार विकास विभाग जल संसाधन विभाग में लगभग 800 कर्मचारी अधिकारी खिलाड़ी कोटे से नौकरी कर रहे हैं। जिसमें 10-20% लोग ही कार्यालय में कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। 70-80% खेल के नाम पर महीनों कार्यालयों में उपस्थित ही नहीं होते। जिससे कर्मचारियों अधिकारियों के रहते हुए भी दोनों विभागों का कार्य बुरी तरीके से प्रभावित होता है। जबकि अधिकांश खिलाड़ी बूढ़े हो जाने के कारण खेलने में सक्षम ही नहीं है। हर साल प्रदेश के 1 संभाग में जनवरी-फरवरी माह में औसतन रु 40-50 लाख हजम करने के लिए केवल खेलों की औपचारिकताएं पूरी की जाती है। जिस में 800 में से 80 खिलाड़ी भी खेलने नहीं पहुंचते। पर होटलों में खाने पीने और ठहरने की 800 खिलाड़ियों के फर्जी बिलों की व्यवस्था की जाती है, औसतन रुपए 12 से 15 लाख के खेल सामग्री क्रय, मुफ्त से लेकर रु 100- 200से लेकर हजार रु.रोज तक में मिलने वाले निगम के स्टेडियम, कैरम, शतरंज हॉल, बैडमिंटन, लॉन टेनिस कोर्ट के बिल भी रु 2हजार से 15000 प्रतिदिन के हिसाब से बनाए जाते हैं, टेटो, फर्नीचर, आदि की लाखों के फर्जी बिल के बनाए जाते हैं पुरस्कारों का वितरण होता है। आशिक अली के गिरोह में राजू सालगांवकर, जोकि इंदौर संभाग के ऊपर काडा में बाबू है। मध्यप्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से भी वेतन लेता है। जोकि सरकार के साथ छल व षडयंत्र है। कोई भी सरकारी कर्मचारी शासकीय पद पर रहते हुए दूसरे लाभ एवं वेतन प्राप्त नहीं कर सकता। पर बंदा सालों से दो वेतन ले रहा है। मुख्य अभियंता कार्यालय का घनघोरिया, देपालपुर उप संभाग का उपयंत्री जो पिछले 20 वर्षों से इंदौर में, इंदौर संभाग के मुख्यालय का प्रभार संभाल रहा है। पिछले फरवरी माह में आयोजित खेल प्रतियोगिता में 90% पैसा 5 लोगों ने मिलकर, फर्जी बिलों से हजम कर लिया। सन 2012 में भी मंडलेश्वर में आयोजित खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन में रु17,81,885/- मै से खर्च मात्र रु 2 से 2.5लाख किया गया। बाकी सारा पैसा बंदरबांट मे हजम कर लिया गया। खेल मैदानों के नाम पर इंदौर स्पोर्ट्स क्लब का रु3 लाख 51 हजार 630/- का नगद भुगतान दिखाया गया, आरबी पचोरकर को पुरस्कारों की ट्रॉफी, आदि का रु 175380/भी, भोलु महाराज भोजन का रु. 45000/- विमल स्टोर्स बैनर बैच झंडे झंडी आदि का रु1,19,050/ - दत्त टेंट हाउस को रु 3,17,850/- आदर्श फोटोकॉपी को रु13200/ - निलेश सिंह चौहान फोटोग्राफर को रु20 हजार का, श्यामा टूर्स एंड ट्रैवल्स को रु48,800/-- सभी की तारीख 23 /4/12 को नगद भुगतान दिखाकर यथार्थ में वह पूरा पैसा हजम कर लिया गया।

दूसरी तरफ अधिकांश खिलाड़ियों की उम्र 58 साल से ज्यादा हो चुकी है। 9 फरवरी 19 में इंदौर में पूरे प्रदेश के खिलाड़ियों के टूर्नामेंट आयोजित किए गए थे। इसकी स्वीकृति रुपए 39.36 लाख की प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग ने, मुख्य अभियंता नर्मदा ताप्ती कछार को, उसने इंदौर संभाग को दी थी। उस समय आशिक अली जो कि नर्मदा घाटी विकास संभाग 20 मंडलेश्वर का उप संभाग 36 का इंदौर स्थित कार्यालय का बाबू हे। पिछले 20-30 सालों से, लाखों रुपए की फर्जी यात्रा बिलों के माध्यम से जीम रहा है। हर साल लाखों रुपए की यात्रा व्यय और भत्तो के भुगतान कार्यपालन व सहायक यंत्रियों के साथ मिलकर संभाग क्र. 20, 30,32, आदि से सालों से किए जा रहे हैं। इस वर्ष भी इंदौर संभाग कार्यपालन यंत्री अग्रवाल और एम सोनी सहायक यंत्री द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। जिसने फर्जी तरीके से बिना टेंडर बुलाए, आर्मर स्पोर्टस से ?10 लाख से ज्यादा की केवल खेल सामग्री, ट्रैकसूट आदि खरीदे गए, इन सब की जांच करवाई जानी चाहिए यदि शासन अपने स्तर पर नहीं करवा सकता, तो मामला आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो और लोकाायुक्त को भी सौंपा ही जायेगा। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य इस फर्जीवाड़े के साथ ही 800 कर्मचारियों अधिकारियों का लगभग रु 10 करोड प्रतिमाह से ज्यादा का जन धन से दिए जा रहे वेतन भत्तो वेतन इन खिलाड़ियों पर खर्च करने के उपरांत क्या लाभ जनता और शासन को मिल रहा है। अधिकांश खिलाड़ी खेल के नाम पर अपने शासकीय कार्य से 70-80% समय तक गायब रहते हैं। लाखों रुपए हर साल का खेल के नाम पर गबन व हजम करते हैं। बदले में अधिकांश कर्मचारी जो खेल कोटे से भर्ती हुए, ना तो मैदानों पर पाए जाते हैं, न खेलते हैं। अपने अपने व्यक्तिगत व्यवसाय में संलग्न रहकर दोहरी कमाई कर रहे हैं। इसलिए बेहतर होगा की इन खेल संघों को को भंग कर दिया जाए। सभी खिलाड़ी कोटे के कर्मचारियों अधिकारियों से पहले शासकीय काम लिया जाए। यदि उन्हें अपना खेलने का शौक व अभ्यास करना है। तो कार्यालयीन समय के पूर्व और पश्चात पूरा करें।

एक देश एक चुनाव कदापि नहीं और कभी नहीं

पेज 1 का शेष

और आपको खाने के लिए इस तरह खराब कचरा माल आपको परोसें और इस भेड़ियों का झुंड पार्टी के सूअर उस में 25 से 50% मोटा कमीशन लेकर विदेशों में मौज करें। जैसे सूअर की औलाद मोदी ने पिछले 5 सालों में 100% विदेशी निवेश फुटकर व्यवसाय में लाकर देश के उद्योग धंधे व्यापार को नष्ट कर, चीनी माल को 25% कमीशन पर भारत में बिकवाने देश के उद्योग धंधों और लोगों को बेरोजगार करने नोटबंदी की गई।

जिसकी आड़ में उन्होंने कम से कम रु. 5लाख करोड से अधिक नोट छाप कर पहले ही आंटी कर लिए। देश में 50 करोड़ लोगों को पूर्णताः बेरोजगार बनाकर उत्पादन ठप कर दिया गया। नकदी की कमी से 50 लाख से ज्यादा छोटे उद्योग पहले ही बंद हो चुके थे उसका फायदा भी पूंजी पतियों को ही मिला उनके फायदे के लिए पुणे बाद में जीएसटी लादकर इस देश को तबाह किया गया आज तक 2 साल बाद में भी उससे छोटे उद्योग धंधे व्यापार के नष्ट होने से जनता उबर नहीं पा रही है।

स्वाभाविक है। एक साथ लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम और पंचायत तक के चुनाव, करवाये गये तो ज्यादा बड़ी तबाही मचायेंगे।

एक ही कोड से सारी इवीएम में केवल कमल और चारों तरफ डकैतों की फौज होगी। फिर कैलाश का मदन गोपाल बल्ले से सरकारी अधिकारियों को पीटेगा भी, और पुलिस और न्यायालय उसकी बहादुरी को सैल्यूट करते, पोस्टर थानों के बाहर और पूरे शहर में लगाकर उसका स्वागत करेंगे फिर कोई कमलनाथ या कांग्रेस सरकार विरोध करने वाली नहीं होगी।

यह याद रखो। बेशक चुनाव में अगर खर्च होता है तो देश की जनता का पैसा देश की जनता को ही बंटता है। वैसे भी भेड़ियों को देश की जनता जिंदा हो या मुर्दा उसे नोचने से काम होता है।

इसलिए चुनाव विधानसभाओं के अलग और लोकसभा के अलग होने ही चाहिए ताकि भेड़ियों का झुंड एक साथ पंचायतों नगर पालिका और निगमों विधानसभाओं से लेकर लोकसभा तक सब को जीत कर देश को पूर्णता बेचकर हजम न कर सके।

इस षड़यंत्र का सूत्रपात् हर सत्ताधारी करता है यह वही भाजपा है जिसने पहले इंदिरा गांधी के टाइम में इस बात का विरोध किया था आज वह सत्ता में है तो उसे पंचायतों नगर निगम पालिकाओं, विधानसभाओं और लोकसभा तक कब्जा जमा कर, पूरे देश को बेच व गिरवी कर तांडव करने की इच्छा हो रही है। इसलिए तत्काल में मेरी बात कभी किसी को समझ में नहीं आई।

साप्ताहिक समय माया

मध्यम वर्ग को निचौड़ा युवाओं को स्वरोजगार का कटोरा...

पेज 1 का शेष

देश के 66000 गांवों में से अधिकांश गांव प्राथमिक शिक्षा के लिए ही तरस रहे हैं। गांवों में अगर भवन हैं। तो शिक्षित और योग्य, पर्याप्त शिक्षक नहीं है। इस बजट में सरकार ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और न हीं उसके लिए कोई धन राशि का प्रावधान किया गया जो देश की भावी उन्नति में अति आवश्यक था। इससे बजट पेश करने वाली सरकार उसके वित्त मंत्री की योग्यता व मानसिक स्तर का अंदाजा लगाया जा सकता है। बड़े पूंजीपतियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मोटे लाभ और उच्च शिक्षित कठपुतली गुलामों की फौज की तैयारी के लिए बेशक उच्च शिक्षा की तरफ धन का आवंटन और व्यवस्था अवश्य की गई।

देश के 29 राज्य की व 7 संघ शासित सरकारों के सौ से ज्यादा विभागों में लगभग एक करोड़ से ज्यादा स्थाई पद खाली पड़े हुए हैं। जिसमें 40लाख पद केवल बाबुओं कंप्यूटर ऑपरेटरों के, हर विभाग में, 20 लाख शिक्षकों के, 20 लाख पद, उपयंत्री, सहायक यंत्रियों, के पद लोक निर्माण लोक स्वास्थ्य, ग्रामीण यांत्रिकी, विद्युत, गृह निर्माण मंडल, नगर निगम पालिकाओं आदि में, 2 लाख डॉक्टरों, 5लाख नर्सों, 3लाख स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ताओं के साथ ही कृषि, उद्यानिकी आदि में 2लाख पद कृषि वैज्ञानिकों के रिक्त पड़े हुए हैं। यही हाल राज्यों के पुलिस के, वन विभाग आदि में 10लाख पद खाली पड़े हैं। जहां स्थाई भर्ती की अपेक्षा युवाओं से 5-10-15 सालों से दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम तो लिया जा रहा है। उनका जीवन बर्बाद किया जा रहा है और उन्हें न्यूनतम वेतन देकर 10-12 घंटे काम किया जा रहा है। परंतु उनको ना तो स्थाई किया जा रहा है। और ना ही पूरा वेतन दिया जा रहा है अन्य समकक्षों के बराबर, यही हाल केंद्र सरकार की रेलवे, जहां लगभग 2लाख इंजीनियर, 5लाख बाबू, 500000 से ज्यादा गैंगमैन, लाइन स्टाफ, इलेक्ट्रिशियन, तकनीशियन आदि की आवश्यकता है। परंतु रेलवे में पदों पर भर्ती करने की अपेक्षा, यह भुखेरा जन पार्टी की फौज इतने बड़े और महत्वपूर्ण विभाग में निजीकरण लागू करने, रेलवे की लाखों अरब की संपत्तियों को बेचने के लिए, मोटा लाखों-करोड़ों कमिशन हजम करने, सब को नजरअंदाज कर पूरा रेलवे का ढांचा बिगाड़ने पर तुली हुई है। यही हाल केंद्रीय विभागों यथा डॉक, श्रम, लोक निर्माण विभाग, आयकर, कस्टम व एक्साइज व अन्य विभागों के हैं। वह चाहती तो आसानी से दो करोड लोगों को देश के 29 राज्यों के, व 7 संघ शासित प्रदेशों के विभिन्न विभागों में रोजगार देकर, देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने में 5 अरब करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाने में सफलता पा सकती है। क्योंकि दो करोड़ लोगों को रोजगार देने से ही देश में आसानी से करोड़ लोगों की क्षमताओं को बढ़ाकर, अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सकता है। इसके विपरीत बहुराष्ट्रीय कंपनियों के इशारे पर नाच कर, उनके मोटे लाभ और देश को गुलाम बनाने के लिए कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेलवे, बिजली-पानी, सड़कें आदि आधारभूत आवश्यकताओं का स्वामित्व बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंपकर निजीकरण कर पर तुली है। भेडियों की सरकार। यह गुलामी सामने से अपने मोटे लाभ के लिए बुला रही है। कांग्रेस ने देश को आजाद किया पर यह भुखेरे इस पंचवर्षीय शासन के अंत तक पूरा देश गुलाम बना देंगे। उसी की तैयारी का बजट है,यह।

भुखेरा जन पार्टी का रु1.5 करोड़ लेनदेन वाले 3करोड खुदरा को व्यापारियों को बेरोजगार बनाकर उनको 3000 मासिक की पेंशन देने की षड़यंत्र के पीछे देश का सारा फुटकर व्यापार 25% कमीशन पर बड़े उद्योगपतियों पूंजीपतियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंपने का षड्यंत्र 2015 में 100% विदेशी निवेश के साथ ही शुरू हो गया था।

घोर मक्कार मोदी ने 2019 मैं सत्ता संभालते ही, अपनी विदेशों में मौज मस्ती और देश को गुलाम बनाने भारत के दस करोड किसानों से कृषि भूमि छीनकर 100३ बहुराष्ट्रीय कंपनियों का निवेश करवाने उस पर ठेकेदारी पर यांत्रिक खेती करवाने का षड्यंत्र रच दिया है। इसलिए 10 करोड किसानों में से मात्र 0.0000001% कृषि उद्यमिता का विकास की बात कही है। बाकी 10 करोड़10 बेरोजगार किसानों को रु1/- किलो गेहूं रु2/- में चावल 100 दिन का मनरेगा में रोजगार ?3000 मासिक पेंशन देकर सब को घर बैठा नकारा, निकम्मा बना देने की नींव का हिस्सा है यह बजट। स्टार्टअप के नाम पर युवाओं को जो दिवास्वप्न दिखाये हैं। युवाओं को रोजगार के लिए बैंकों से जो ऋणों की व्यवस्था दी गई है। वह आज से नहीं 1980 से लागू है। परंतु बैंकों में बेरोजगारों को ऋण लेने के लिए, जिला उद्योग केंद्रो, नगर निगम पालिकाओं में भारी चक्कर कटवाए जाकर, भारी भ्रष्टाचार से वसूली की जाती है। यदि महीनों चक्कर काटने के बाद उसे ऋण मिल भी जाता है।तब तक वह मानसिक, शारीरिक रूप से टूट चुका होता है। फिर भी वह यदि छोटा-मोटा उद्योग लगा लेता है। तो उद्योग या व्यवसाय करता है। तो चला नहीं पाता और अंत में परेशान होकर युवा या तो आत्महत्या कर लेता है। या छोटी-मोटी नौकरी में जीवन खपा देता है।

जब तक जब तक मोदी सरकार पूंजीपति और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कठपुतली बनकर नाचना नहीं छोड़ेगी तब तक इस देश का, युवाओं का, छोटे लघु मध्यम व ग्रामीण उद्योगों का विकास संभव नहीं।

यह धूर्त मोदी अगर विदेशों में जाकर मौज मस्ती नहीं करता। देश के, युवाओं के, उद्योग धंधों के विकास पर ध्यान देता तो सबसे पहले चीन से व अन्य देशों से होने वाले छोटे-मोटे, व बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल्स, खिलौने, वस्त्र सामग्री, रक्षा सामग्री व अन्य सामानों के आयातों के विकल्प ढूंढकर उन सब का उत्पादन देश में ही शुरू करवाता। जिससे देश के करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता, विदेशी मुद्रा की बचत होती, उन सामानों का निर्यात बढ़ता, तू विदेशी मुद्रा की आय भी होती। उसका मैक इन इंडिया जा दिखाया गया। सपना साकार होता। पर दुसरी पंचवर्षीय सरकार के बजट से यह सब साफ हो चुका है कि उसे देश के करोड़ों बेरोजगार युवाओं से देश की वास्तविक उन्नति से कोई सरोकार नहीं। उसका शुरू कर दो केवल देश की जनता को भ्रमित कर, पाकिस्तान और चीन का डर दिखाकर विदेशों में, मुख्य रूप से अमेरिका, रूस, चीन, जापान, फ्रांस, आदि देशों में अपनी मौज मस्ती करने, अपने पूंजीपति मित्रों के लिए, 132 करोड़ की आबादी के देश के प्रधानमंत्री होने के नाते, उनका व्यवसायिक प्रतिनिधि बनकर नए व्यावसायिक सौदे करने के बदले में, जिसकी लाखों करोड़ की विदेशी मुद्रा बर्बाद कर वहां से विदेशी तकनीकी व हथियारों का समय बाधित, पुराना कबाड़ा खरीदने में बर्बाद करता है। जबकि उसका लोहा व अन्य धातुयें, तकनीशियन सब भारत के होते हैं। उनसे बेहतर तकनीकी के हथियारों का निर्माण भारत में किया जा सकता है। पर अपने 95% तक के कमीशन के लिए ऐसा होता व किया नहीं जाता।

सर्वोच्च न्यायालय का स्थगन, आरक्षित वर्ग को पदोन्नत न करने पर

शासन करे सभी विभागों में पदोन्नतियां, 80% अधिकारी प्रभार में...

कांग्रेसियों ने सत्ता संभाल कर सभी विभागों में सेवानिवृत्ति व अन्य कारणो से रिक्त अधिकारियों के पदों पर, सर्वोच्च न्यायालय में लगे हुए स्थगन आदेश को समाप्त करवाने की अपेक्षा घोर भ्रष्ट मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्री, प्रधान सचिव, संचालक, प्रमुख अभियंता आयुक्त सभी विभागों में अधिकारियों के पदों पर पदोन्नति देने की अपेक्षा प्रभार के खेल से मोटी कमाई कर रहे हैं। बेशक इस खेल का असली खिलाड़ी दिग्गी दानव ही है। मध्य प्रदेश में 15 साल के बाद कांग्रेस के सत्ता संभालने से, सभी शासकीय कर्मचारियों अधिकारियों में भारी हर्ष व्याप्त था। कि नई सरकार आने के बाद शायद वर्षो से रुकी हुई पदोन्नतियां सभी को समान रूप से मिल सकेंगी। क्योंकि 13 साल तक मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज को जो अहंकार उत्पन्न हो गया था। जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत अहंकार के वशीभूत हो बड़े-बड़े मंचों से दहाड़ने लगा था। कि कोई माई का लाल मध्यप्रदेश में आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। उस अहंकार की दहाड़ ने हीं शिवराज को सत्ता से ही बाहर कर दिया।

मध्यप्रदेश की विधानसभा से 15 वर्ष पूर्व में कांग्रेस की जाने का मूल कारण था। दिग्गी दानव की लूट खसोट भरी बदतमीजी पूर्ण कर्मचारियों अधिकारियों को प्रताड़ित करने, उन्हें समय पर पदोन्नतियां महंगाई भत्ते, वेतनमान ना देने की कार्यशैली, जिसने पूरी कांग्रेस को ना केवल प्रदेश में वरन देश में भी खदेड के बाहर कर दिया। जबकि इसी गुरु मंत्र से सत्ता में भुखेरा जन पार्टी की शिवराज सिंह सरकार ने 3 कार्यकाल पूरे किए। पर जब अंतिम कार्यकाल में उसने भी सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों की अपेक्षा करना शुरू कर दिया तो वह भी बाहर हो गया। यथार्थ में नेता विधायक मंत्री मुख्यमंत्री सरकार नहीं चलाते, ये केवल अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। सरकार प्रशासन में बैठे अधिकारी और कर्मचारी ही चलाते हैं। वर्तमान में भी मुख्यमंत्री भले ही कमलनाथ हो परंतु सरकार में पूरा हस्तक्षेप और नियंत्रण महा धूर्त दिग्गी दानव का है। जो ना केबल कमलनाथ को इसकी सरकार को गिराकर और बर्बाद करके ही मानेगा।

अब जबकि सभी शासकीय विभागों में 20-30% ही सवर्ण रह गये हैं। तो यह शूकर दिग्गी दानव 20% सवर्णो की भर्ती पिछाडू दरवाजे से सीधी करके दिखाएं। जैसे कि उसने अपने कार्यकाल में आरक्षित वर्ग की, की थी। दूसरी तरफ जो 20-30% ही सवर्ण कार्यरत कर्मचारी अधिकारी हैं।उनको सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत आरक्षण के हिसाब से ही तो कर दे। परंतु न्यायालय के स्थगन की आड़ में पदोन्नतियां रोककर मोटी बसूली करने के लिए सब का भविष्य बर्बाद करना कहां का और कैसा औचित्य है। वैसे भी शासकीय विभागों में अधिकांश कर्मचारियों अधिकारियों की राय है जब तक या तो सरकार गिर जाए या यह दानव देह त्याग ना कर दे। प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलने वाला।

दुनिया चीन का माल खरीदना करो बंद उसकी दादागिरी का करो अंत

पेज 1 का शेष

और मौका आने पर उन्हें चटकाने और उड़ा देने की करने की तैयारी रखता है उसके वन बेल्ट वन रोड वन बेल्ट, सिल्क रूट, 140 देशों में रेल लाइन, सारे प्रोजेक्ट दूसरे देशों को अपने जाल में फंसाने की तैयारी में पिछली 4 सदियों से लगे हुए हैं। भारत से जुड़ी हुई 4642 किमी ऊपर की सीमा पर सटे हुए भारत के प्रदेश इसमें तिब्बत भूटान सिक्किम को तो अपना सब बताता ही है भारत के अरुणाचल प्रदेश को भी वह अपना ही समानता है वहां के नागरिकों को चीन में आने जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। हाल ही में भारत के एएन32 विमान को चटकाने का कारनामा उसने फिर दोहराया जो पिछले 30 सालों से लगातार चल रहा है। बेशक भारत में चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या भाजपा की सरकार चीन के नाम से सभी बहुत डरती है। डब्ल्यूटीओ या विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से उसने जो खेल पूरी दुनिया में अपने माल को जो सस्ता बनाए जाने के कारण स्तर हीन अविश्वसनीय उपयोगकर्ता की हर स्तर पर गोपनीयता को चुराने वाला जासूसी करने वाला इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें मोबाइल से लेकर सेवा प्रदाता कंपनियों के अधिकांश उपकरण रक्षा उपकरण आदि सामान बेच रहा है। उसको तत्काल दुनिया में बंद कर दिया जाना चाहिए। ताकि चीन की आंतरिक अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो जाए। भारत को घेरने उसकी अर्थव्यवस्था चौपट करने सामरिक रूप से उसकी सीमाओं पर नियंत्रण करने भारत से सटे देशो जिसमें नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका आदि को लगातार आर्थिक वित्तीय सामरिक सहायता देने के साथ भारत को घेरने के लिए उन देशों में अपनी भाषा संस्कृति का भी विकास करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम लगातार पिछले कई सदियों से चलाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में चीन के खिलाफ न केवल प्रदर्शन हुए उसके उत्तरी क्षेत्र में बनाने वाले प्योंगडोंग से कराची तक के सड़क के विकास में कई पाकिस्तानी गुटों ने चीनी सेना और वह सड़क मार्ग बनाने में इंजिनियरों और मजदूरों की भी हत्या खुलकर की। इसके विपरीत श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, जहां पर वह साम, दाम, दंड, भेद से ना केवल अपना एक बड़ा बाजार विकसित कर चुका है। वरन वहां पर अपनी भाषा संस्कृति का विकास में भी लगातार वित्तीय सहायतायें उपलब्ध करवाकर से वहां पर चीनी लोगों की कालोनियां नेपाल बांग्लादेश श्रीलंका मैं बना देगा और फिर वही चीनी नागरिक धीरे धीरे वहां की सत्ता पर ऑस्ट्रेलिया की तरह कब्जा करने का षडयंत्र शुरू कर देंगे। बेहतर होगा कि यूरोप के सभी देश, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, और एशियाई महाद्वीप के सभी देशों को चाहिए चीनी साम्राज्यवाद की नीतियों से तत्काल सावधान होकर सारा चीनी माल आयात करना बंद कर दिया जाना चाहिए। सबसे पहले यूरोप कोरिया जापानी कंपनियों को चीन में सस्ती मजदूर सस्ता कच्चा माल मुफ्त की बिजली कर छुटो का लाभ लेने की बजाय वहां पर अपना सभी प्रकार के उत्पादन बंद करना चाहिए और धीरे-धीरे चीन से सारे संबंध खत्म करनी चाहिए अन्यथा अमेरिका का दुनिया पर साम्राज्य खत्म करने का सपना तो बहुत दूर उल्टे अमेरिका और यूरोप के अनेकों देश चीनी गिरफ्त में आ जाएंगे। यदि दुनिया के सारे देशों में चीनी माल खरीदना बंद कर दिया तो स्वाभाविक है आर्थिक टूटने के कारण उसकी साम्राज्यवादी नीतियों पर लगाम लगाई जा सकेगी था एशियाई देशों में उसके पड़ोसी मुझसे दोस्ती कर मैं आसानी से उसके चारों तरफ फैली छोटे-छोटे देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, कोरिया, ताइवान, वियतनाम, फिलिपींस, मलाया आदि को डरा धमकाकर कब्जे में लेने के बाद भारत में भी वह आने वाले समय में भारत पर भी अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश करेगा। यह सच है, कि भारत की सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु, दिल्ली-मुंबई, गुरुग्राम, कोलकाता, पुणे, इंदौर के पीथमपुर में अनेकों चीनी फैक्ट्रियां है। इस देश के अनेक नगरों में चीनी नागरिक लाखों की संख्या में कार्यरत हैं जिस पर सरकार की नजर नहीं है। वे यहां काम करने नहीं यहां की भौगोलिक परिस्थितियों को समझने के साथ यहां के नागरिकों की मानसिकता और अपने पैर जमाने के लिए षडयंत्रों की रचना में अपने चीनी मोबाइलों के माध्यम से डाटा एकत्रित कर रहे हैं। यह बात यहां के घोर धूर्त मक्कार और भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारियों, सत्ता में बैठे नेताओं मंत्रियों से लेकर प्रधानमंत्री तक को समझ में नहीं आएगी परंतु उनका षड्यंत्र 3 सदियों से लगातार चल रहा है सरकार को और जनता को इससे सावधान रहने की जरूरत है अनेकों इंदौर में बसी हुई आईटी कंपनियों में अपने चुनाव प्रचार के दौरान चीनी नागरिक देखे गए जो मैंने चुनाव प्रचार के समय जाना।

डॉक्टर नहीं गिद्ध- देश के 50 करोड़ गरीब पशुओं पर चल रहा मौत का व्यापार

औषधि परीक्षण की प्रयोगशालाएं हैं, निजी और सरकारी चिकित्सालय

टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल मे 1986 से कैंसर के मरीजों पर ड्रग ट्रायल कांड किया जा रहा है। और उससे करोड़ों रुपए की दवाइयां तैयार करके बेची जा रही है।भारत के चिकित्सा क्षेत्र का यह सच देश और दुनिया को नहीं मालूम।

देश का पहला अस्पताल था।जहां ड्रग ट्रायल कांड शुरू किया गया। कैंसर के मरीजों पर। मरे तो देश के कैंसर मरीज और दवाइयां बनी तो विदेशों की और अमेरिका की कैंसर बनाने वाली कंपनियों के काम आई। यह कड़वा सच भी टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल का ही है जहां सस्ते के नाम पर सैकड़ों मरीज हर साल ट्राइल के शिकार होकर मृत्यु को आलिंगन करते हैं। इस सच की खोज मुझे लोगों ने जब सन 2008-9 मई इंदौर में ड्रग ट्रायल कांड पकड़ा गया। तो लोगों ने मुझे कुछ जगह घेर के रख दिया और बोले अजमेरा जी यह सब ऊपर ऊपर चल रहा है। इसकी जड़ से खोदकर खोज बीन करके सचाई आप लिखिए मैंने उनको वादा किया और 15 दिन तक लगातार दुनिया की बहुत सारी साइटें खोल कर इस पर पूरा अनुसंधान करने के बाद जब वह रिपोर्ट चिपकाई। तो मालूम पड़ा देश के सरकारी और निजी करीबन तीन लाख से ज्यादा चिकित्सालयों में करीब हर दिन 20 लाख से ज्यादा मरीजों पर डब्ल्यूएचओ को चलाने वाली कंपनियों की दवाई उनकी उपयोगिता जांचने के लिए उपयोग में लाई जाती है। जिसका भारी मोटा पैसा सरकारी और निजी चिकित्सालय के डॉक्टरों को मिलता है।

बाद में गहन अध्ययन के बाद में उसका निष्कर्ष निकाला गया कि देश में 25ङ्म मरीज ड्रग ट्रायल का शिकार होकर मौत को प्राप्त करते हैं।अस्पतालों से निकलने वाले शवों में। सरकारी में तो कांड खुल भी जाते हैं।

परंतु निजी मेडिकल कॉलेज में बड़े अस्पतालों में 6 अप्रैल 2004 के बाद से जब से स्वास्थ्य मंत्री अंबु मणि रामदास ने ड्रग ट्रायल को सभी चिकित्सालयों में भारत में बिना किसी कानून और व्यवस्था के मुक्त कर दिया था। निजी चिकित्सालय में किडनी हर्ट लीवर आंखें गरीब एकल कमजोर वर्ग के लोगों की निकालकर करोड़ों रुपए में बेचने के अड्डे छोटे जिलों से बड़े जिलों में सब जगह चल रहे हैं।और बाद में उसकी मृत्यु बता कर उसको बांधकर उनके रिश्तेदारों को सौंप दिए जाते हैं लाइलाज बीमारी से मर गया खोलना मत इसे और सीधे जला देना। कह कर जलवा दिये।

इंदौर तो इस कांड का बड़ा अड्डा रहा है। यहां पर तो प्रशासनिक स्तर पर ही घायल लोगों को इंजेक्शन देकर ब्रेन डेड बताकर उनके मां-बाप को आसानी से बहला-फुसलाकर हस्ताक्षर करवाकर अंगदान करने के नाम जीवित घायल युवाओं को मेदांता जैसे कसाई खानों में हार्ट, लिवर , किडनी, आंखें निकालकर बेंच के हजम कर गए। जिसमें प्रशासन ने भी पूरा साथ दिया उस समय इंदौर संभाग आयुक्त संजय दुबे हुआ करता था। जब मैंने इस कांड को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिपकाया तब जाकर कहीं ये कांड बंद हो पाये। नहीं तो हरामखोरो न हीं ऐसे अधघायल युवाओं को मारकर उनके किडनी,लीवर, हर्ट, आंखें, निकालकर ग्रीन कॉरिडोर बनाकर वाहवाही लूटी और उनको अहमदाबाद दिल्ली मुंबई व अन्य बड़े शहरों में बैचकर करोड़ों रुपए कमाए।15 साल से यह कांड लगातार देश में हर दिन लाखों चिकित्सालय में चलता रहता है। पर कहीं कोई देखरेख रेख पकड़ धकड़ जांच परख पूछताछ कुछ भी नहीं है। इस देश में इसलिए खुले में सब कुछ चल रहा है और जनता पैसे देकर शिकार होकर मर भी रही है।

सरकारी सफेद एप्रिनके गिध्दों का तांडव

जनधन से वेतन व 25% तक नान प्रेक्टिस भत्ते फिर भी निजी को सेवायें

मध्य प्रदेश का जाना माना इंदौर का एम वाय हॉस्पिटल एवं गांधी चिकित्सा महाविद्यालय जहां के घोर निकंमे डाक्टर्स अपनी निजी प्रैक्टिस में आजू बाजू के निजी अस्पतालों में सेवायें देकर रु 2 हजार- प्रति घंटे से लेकर रु 5 से 20हजार तक की मोटी कमाई कर रहे हैं।

चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय के सारे घोर मक्कार, घोर स्वार्थी, लालची शूकरों की फौज जन धन से वेतन लेकर निजी चिकित्सालयों में सेवायें दे रही है। बेचारे गरीबों के नवजात शिशुओं व 5 वर्ष तक के बच्चों को वहाँ कोई देखने वाला डाक्टर व नर्सों तक अब वहाँ नहीं मिलता। वे ही इक्का दुक्का नर्सें मोटे कमीशन पर निजी कसाई खानों में भेज देती हैं। डॉ. हेमंत जैन जो कि नेहरू चिकित्सालय का मुख्य चिकित्सा अधिकारी है। 56 दुकान

के पीछे बना डॉक्टर संजय कासलीवाल के डाल्फिन हास्पिटल 12 घंटे के रु. 20000/- वसूलता है। नवजात बच्चों की चिकित्सा के। हरामखोर वहां अपनी सेवाएं देता है।

अनेकों प्रकरणों की जानकारी प्राप्त हुई है। गरीब मां बाप अपने बच्चों को कर्ज लेकर इलाज करवाने पर मजबूर हैं। पर वहाँ पर एम वाय चिकित्सालय के वही डाक्टर मोटी फीस पर इलाज करते मिल जायेगें। सच तो यह भी है कि एम वाय के चिकित्सकों के दम पर ही 200 से ज्यादा निजी चिकित्सालय या आधुनिक चिकित्सा के नाम चल रहे कसाई खाने हैं। जो कि एम वायहास्पिटल की 5 किमी की परिधि में बने हुए हैं। इस संबंध में जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से बात करने पर उसने कहा यह सब विजय लक्ष्मी साधो देखती हैं। उनसे बात करिये। स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट का नंबर व्यस्त बताता रहा।

आखिर कब तक चलेगी सरकारी सफेद एप्रिन के इन आधुनिक लूट खसोंट के गिध्दों का यह तांडव। जनधन से वेतन लेकर साथ ही 25% तक नान प्रेक्टिंग भत्तों को लेकर भी ये घोर लालची गिध्द अपनी सेवायें आठ घंटे भी नहीं देना चाहते। बदनाम मंत्री और सरकार होती है। वैसे भी मंत्री को महीना पहुँचाते रहो। करो जो करना है। 15 साल बाद सत्ता आई है। न जाने कब सरकार गिरा दी जाये। अभी तो चुनाव खर्च भी नहीं निकला है।

भोजन और पानी के अभाव में प्रदेश के जंगलों में सैकड़ों बंदरों व वन्य जीवों की मौत

कहां जा रहा विश्व वन्य प्राणी निधि और केंद्र व राज्य का धन, वन प्राणियों के संरक्षण का

मानवीय लालच से कटते और घटते वन, घटती कर्मचारियों, बढ़ती गांवों और जन की संख्या और बढ़ते भारतीय वन हड़पो सेवा के अधिकारी, कर रहे सिमटते वनों और वन्य प्राणियों का चहूंदिशी विनाश। हरामखोर जालसाजों की फौज जो मुख्यालय से लेकर वृत्तों, वन मंडलों, परिक्षेत्र कार्यालयों तक बैठी है।सूचना के अधिकार में आवेदनों और अपीलों पर भी सुनवाई नहीं करती।

मध्य प्रदेश के सभी मैदानी क्षेत्रों के वृत्तों, वन मंडलों, और उसके परी क्षेत्रों के सभी कार्यालयों में 5-10 बरसो ज्यादा समय से बैठे हुए घोर भ्रष्ट कर्मचारी वनपाल वनरक्षक क्षेत्राधिकारीयों का स्टॉफ को सभी रेंजों मैं चूंकि सभी ले देकर बैठे हैं, स्वाभाविक है, वनों की आग से बचाव वन्य प्राणियों, वृक्षों हरियाली आदि के लिए आवश्यक जल स्त्रोतों के लिए राज्य शासन व केंद्र शासन नियोजित व गैर नियोजित मदों में पर्याप्त धन देता है। परंतु वास्तविकता में, वृक्षों, हरियाली, वन्य प्राणियों, पशु, पक्षियों, के दाने पानी के धन के साथ, वनो मैं उगी सूखी घास, वृक्षों के सूखे पत्तों, टहनियों आदि के कचरे की साफ सफाई जो गर्मी के दिनों में जंगल में आग फैलने का कारण बनती है। वनों में वनकर्मियों के वाहन व आवागमन के मार्गों को बनाए रखने कच्ची सड़कें बनाने का पैसा, पर्याप्त पानी की आपूर्ति के लिए चेक डैम, स्टॉप डैम आदि के निर्माण हेतु धन देता है। देवास की पुंजापुरा रेंज में हुए सैकड़ों बंदरों की मौत में भी जल स्त्रोतों व, जलाभाव अभाव के साथ ही कई कारण और भी सामने आए हैं जिसमें बंदरों के सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत एक समूह का जल स्त्रोतों पर, मादाओ पर कब्जा व वर्चस्व के लिए दूसरे समूह से युद्ध करने मैं मौत होना, बीमारी फैलना और लू लगने से भी ना केवल सैकड़ों बंदरों वर न अन्य प्राणियों की मौत भी स्वाभाविक है। वैसे जल स्त्रोतों के संबंध में श्री अजमेरा ने नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के कुछ कार्यपालन यंत्रीयो से चर्चा की घने वनों के बीच से निकलने वाली नर्मदा क्षिप्रा उज्जैनी तक 55 किलोमीटर उज्जैनी से उज्जैन तक लगभग 40 किलोमीटर नर्मदा गंभीर 60 किलोमीटर आदि की पाइपलाइनो से वनक्षेत्रों में भी जलापूर्ति की जाए, ताकि इस प्रकार वन्य प्राणी अकाल मृत्यु का शिकार ना हो।

ऐसे सभी कार्य जो कि ग्रामीण दैनिक वेतन भोगी मजदूरों से करवाई जाती है जिनकी 25 से 40% मजदूरी का पैसा वहां के वन मंडल अधिकारी से लेकर रेंजर व अन्य वन कर्मियों हजम कर लिया जाता है। बेशक वर्तमान में अधिकांश मजदूरों का पैसा सीधा बैंक खातों में पहुंचता है । इसके विपरीत इस ठगी में बैंक वालों को साथ लेकर बहुत सारे मजदूरों के फर्जी नामों से खाते चलाए जाते हैं । और पैसा यहां से से निकाल लिया जाता

है। सूचना अधिकार अधिनियम को लागू हुए 14 साल गुजर जाने के बाद में भी धारा 4 के अंतर्गत अभी तक 17 बिंदुओं की जानकारी विभागीय साइट पर भी अपलोड नहीं की जाती। दूसरी ओर इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, उज्जैन वृत के देवास, शाजापुर, जहां पर अनेकों आवेदन पिछले कई सालों से लंबित होने के उपरांत भी जिसमें वन संरक्षक जानकारी निशुल्क देने के आदेश दे दिए परंतु कभी भी जानकारी पूरी नहीं दी गई क्योंकि वहां बैठा हुआ लेखा शाखा का घोर भ्रष्ट स्टॉफ अपने कुकर्मो को छुपाने और बचाने के लिए समय नहीं मिला का बहाना बनाकर आवेदकों को टरकाता रहता है। वैसे सच तो यही भी है इंदौर के वन मंडलाधिकारी सिसोदिया, उपवन मंडलाधिकारी एल्विन बर्मन, से लेकर सभी रेंजर आदि तक मोटा धन देकर ही पदस्थ किए जाते हैं। तो स्वाभाविक है की वो शासन की आवंटित धन में से, मोटा कमीशन और वन संपदा की बर्बादी से जिसमें वृक्षों की कटाई, वन भूमि पर कब्जे, अवैध उत्खनन आदि से मोटी कमाई करेंगे। जिस के उदाहरण चोरल , मानपुर, नाहर झाबुआ जहां थोड़े अच्छे वन हैं। वर्षों से अवैध कटाई अपनों की जांच वन भूमि पर कब्जों की जांच, इंदौर के गुरु नानक काष्ठ बाजार में आती हुई हर दिन लगभग 300 ट्रॉली हरे कटे हुए वृक्षों की जांच के नाम पर मोटी वसूली की कछुए की गति से जांच चल रही है। मैं अधिकारियों द्वारा स्वयं कर्मचारियों को बचाया जा रहा है। क्योंकि सभी का हिस्सा है उसमें । क्रमशः

साप्ताहिक समय माया

वाणिज्य कर में 3-5 साल से ज्यादा समय से बैठे सौ से ज्यादा अधिकारी

क्यों नहीं होते 5-7 वर्षों से ज्यादा से बैठे अधिकारियों के स्थानांतरण

हर 5-10 दिन में परिवर्तन के कारण जीएसटी से न केवल व्यापारी वरन् अधिकारी और कर्मचारी भी परेशान है, अधिकांश कर्मचारी अधिकारी रोज-रोज की मीटिंग और बुलाबे से इंदौर के कार्यालयों में पदस्थहैं। उकता चुके हैं। छोटी और शांति वाली जगह पर काम करने के इच्छुक हैं अधिकांश। क्योंकि जीएसटी में कोई कार्य बचा ही नहीं है तो कमाई के स्त्रोत भी बंद हो चुके हैं। इसलिए अधिकांश कर्मचारियों और अधिकारियों का इंदौर में रहने का आकर्षण समाप्त हो चुका है।

इंदौर वाणिज्य कर के मुख्यालय में सारे प्रदेश के घोर धूर्त मक्कार अधिकारियों कर्मचारियों का 5-7 वर्षों से लेकर 20 बरसों से जमावड़ा लगा हुआ है। इन हरामखोरों की फौज सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर, अपने भ्रष्टाचार जालसाजियों को छुपाने केवल बहाने, मक्कारी व जानकारी न देने के लिए स्पष्ट लिखकर देती है कि हम जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं। जब की धारा 4 में यह 17 बिंदुओं की सारी जानकारी 14 वर्ष के बाद भी घोर धूर्त मक्कार वाणिज्य कर आयुक्त से लेकर अधिकारियों कर्मचारियों ने अभी तक वाणिज्य कर की साइट पर लोड नहीं की, न हीं लोड करने का लोड लिया।

मध्यप्रदेश वाणिज्य कर मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालयों में अधिकांश अधिकारी जिसमें स आ दीपक श्रीवास्तव, विनीता जैश, राखी कसेरा, पूर्णिमा चौरसिया, बबीता पटेल, रूबी रघुवंशी, पारुल अग्रवाल, प्रीति जौहरी, इंदु जैन, निशा चौहान, अनुराग पाठक, धूम सिंह चौहान, निनामा, उपायुक्त अब्दुल मजीद व पूरे प्रदेश में ऐसे सौ से ज्यादा अधिकारी 2004 बैच के 2005 बैच के 8 बैच के अधिकारी जो एसीटीओ सीटीओ से लेकर सहायक आयुक्त उपायुक्त संयुक्त आयुक्त तक भ्रष्टाचार का का मोटा धन बांट कर बरसों से इंदौर में ही जमे हुए हैं। आखिर 3 साल की सेवा के बाद स्थानांतरण के कानून का पालन क्यों नहीं किया जा रहा! स्वाभाविक है, वर्षों से एक ही पद पर एक जैसा कार्य कर कर के अधिकारी-कर्मचारी सभी उस से उकता चुके हैं।

वाणिज्य कर विभाग में स्थानांतरण की सूची मोटा लेन देन कर निकाली गई। वेशक मोटा लेन देन एंटी ईवेजन संभागों में सबसे ज्यादा हुआ। परंतु बरसो से जमी हुई महिला अधिकारियों को ऊपर नीचे दाएं बाएं भेजा गया उनका स्थानांतरण इंदौर से बाहर नहीं किया गया। प्रदेश के इंदौर आने का इंतजार कर रहे बाहर के पुरुष अधिकारियों व कर्मचारियों का स्थानांतरण संभव नहीं हो सका। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व वाणिज्य कर आयुक्त, महिला प्रेमी घोर अय्याश शैलेंद्र सिंह के इशारे पर किसी भी महिला अधिकारी का स्थानांतरण इंदौर से बाहर नहीं किया गया। जिसका रोष सभी कर्मचारी संगठनों में है!

दूसरी तरफ ना पदोन्नतियां, ना स्थानांतरण, फिर 1 जुलाई 17 से लागू जीएसटी को मोदी सरकार ने, अपने बड़े पूंजी पति मित्रों अदानी अंबानी टाटा बिरला व अन्य और बहुराष्ट्रीय कंपनियों से लाखों करोड हजम कर उनके लाखों करोड के फायदे के लिए देश के 10 करोड छोटे मध्यम बर्गी व्यापारियों, उद्योगपतियों को समाप्त करने के लिए बिना पूर्ण तैयारी और सोच, समझे और बिना विभागीय कर्मचारियों अधिकारियों को सिखाए पढ़ाये कानून बिना तैयारी के थोप दिया! दूसरी ओर भारतीय प्रताड़ना सेवा के अधिकारी जो इस विभाग में आयुक्त अतिरिक्त आयुक्त के रूप में बैठाये जाते हैं। नेता के रूप में बैठे, विभागीय, वित्त व मुख्यमंत्री को जिन्हें केवल मुंह चलाना आता है उनका दूर-दूर तक कार्यालयीन व्यवसाय, मानव संसाधन, लोक वित्तीय प्रबंधन से, दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। अपनी छद्म कार्य की विशेषता, श्रेष्ठता और पद के अहंकार में विभागीय कर्मचारियों अधिकारियों को डांटना ,फटकारना, प्रताड़ित करना, तो उन्हें प्रशासनिक प्रशिक्षण में सिखाया जाता है, इसलिए यह सब उनके लिए बहुत मामूली बात है, से आगे जाकर गैर कानूनी तरीके से, वरिष्ठ संयुक्त, उप, सहायक आयुक्त, से लेकर निरीक्षक और बाबूओं तक सबको कर वसूली, कर विवरणी जमा करने के लिए व्यापारियों, उनके कर सलाहकारों को टेलीफोन करने, कार्यालय बुलाने तक के के लिए मौखिक रूप से डांटते हुए निर्देशित किया जाता है। कर्मचारियों अधिकारियों ने बताया, कि हर महीने 15 दिन में बदलते हुए जीएसटी के नियम, अधिक पेचीदा होने से वैसे भी किसी को समझ में नहीं आ रहा! फिर भी यदि किसी कर सलाहकार और व्यापारी ने बार बार टेलीफोन करने से चिढ़ और परेशान हो कर हमारे हीं विरुद्ध शिकायत कर दी, यह आयुक्त आहूजा जी हमें बचाने नहीं आएंगे। दूसरी तरफ भारत में आयकर संपत्ति कर आदि के लिए भी बड़े विभाग बैठे हुए हैं। परंतु वहां के अधिकारी, कर्मचारी किसी भी करदाता को टेलीफोन करके बुलाते या और जमा करने के लिए नहीं कहते। तो यह सब नौटंकी यह प्रशासनिक अधिकारी केवल वाणिज्य कर में ही क्यों करते हैं? उद्योगपति, विक्रेता, व्यापारी और उनके कर सलाहकार खुद समझदार है। वे स्वयं अपनी जीएसटी की कर देनदारीयों को पूरा करने में सक्षम है! वैसे ही चारों तरफ नोटबंदी और जीएसटी से व्यापार-व्यवसाय उद्योग धंधे सब चौपट पड़े हुए हैं। किसी प्रकार से यह सभी कर दाता अपना अस्तित्व बचाए हुए हैं। हजारों लोगों को रोजगार दिए हुए हैं। उन्हें बार-बार फोन करने से उल्टे ही व्यापारियों की झिडकियां हमें ही सुननी पड़ती है उल्टा ही वह बोलता है पहले मुझे व्यवसाय तो जमाने और करने दो। जब माल बिकेगा तभी जीएसटी देना पड़ेगा ना जब माल ही नहीं बिक रहा है। तो कर कहां से और कैसे दूं। दूसरी तरफ दूसरे, तीसरे, चौथे स्तर के सभी व्यापारी अपने पुराने जीएसटी के रिफंड के करोड़ों रुपए सरकार से पाने के चक्कर में परेशान हुए जा रहे हैं। और उनकी कार्यशील पूंजी का धन सरकार के पास अटका हुआ है। सरकार पहले बह दिलवाये। ताकि हमारे व्यापार के लिए जब तक हम कच्चा माल नहीं खरीदेंगे और उसका भुगतान व क्रेता को माल नहीं भेजेंगे। तो क्या सरकार को मुफ्त का कर को चुकायेंगे! सरदारपुर सरकार को चाहिए की विक्रेता को य ह कानूनन सुविधा उपलब्ध करवाएं, की व्यापारी जो कर अपने विक्रेता या उत्पादक को चुकाया है, वह अपने ग्राहक से केवल अपने लाभ के अंतर का स्वयं भी वह टैक्स ही वसूले और सरकार को बिलिंग के साथ तत्काल चुकाए। ताकि व्यापारी सरकार को पहले वसूली से चुकाना, और बाद में उसकी प्राप्ति के झंझट से स्वयं सरकार को व व्यापारी को भी परेशानी से बचाया जा सके।

जीएसटी के कानून में हर संशोधन के साथ ही हर महीने की आखिरी दिवस को जीएसटी में हुए संशोधन के बारे में पहले अपनी कमजोरियां को दूर कर अपने स्टाफ के साथ कर सलाहकारों, सनदी लेखाकारों को प्रशिक्षित करें। कर दाता को परेशान न करें और यह सच भी है। जिसे प्रदेश और देश के सभी आयुक्तों को समझना चाहिए।

चुनाव खत्म लूट शुरू

देश में नवंबर 18 में 5 राज्यों के चुनाव, मार्च-अप्रैल मई19 में पूरे देश में लोकसभा चुनाव होने के कारण लगातार पेट्रोल डीजल की रुपए 80 और 70 की कीमतें कम की जाती रही। कीमतें कम होती देख कर हर साधारण सा आदमी भी कहता था की चुनाव होना हैं। इसलिए जनता को भ्रमित करने और चुनाव जीतने कीमतें घटाई जा रही हैं। परंतु अब चुनाव खत्म होने अपना भुखेरा जन पार्टी का शासन आने के कारण चुनाव खत्म होते ही, केंद्र व प्रदेश की सरकारों के राजनीतिक दलों ने चुनावी खर्च वसूल करने और अपने पूंजीपति मित्र अंबानी बंधुओं को जो देश के लिए विदेशों से पेट्रो क्रूड खरीदते हैं। सरकारी कंपनियों रिफाइनरी को आपूर्ति करने से पहले ही 10से 20% का मोटा लाभ हजम कर जाते हैं। को भारी लाभ पहुंचाने व सरकार को तत्काल नगद लाभ दिलाने के लिए भुखेरा जन पार्टी की सरकार ने और प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जनता से लूट के लिए पेट्रोल डीजल की कीमतों में केंद्र सरकार द्वारा रु1 सेस व रु1 एक्साइज बढ़ाई तो राज्य सरकार ने रु2-2 कीमतें बढ़ा दी साथ ही शिवराज सरकार द्वारा 28% वेट को नाथ ने 29% किया। जबकि पैट्रोल पर रु4 और डीजल पर रुपए 3 अलग से वसूल किए जा रहे थे। जो बढ़कर 5व4 हो गए।15 वर्ष बाद कांग्रेसियों के भूखों को सत्ता क्या मिली? कि चारों तरफ लूटने खाने में जुट गए। विधानसभा चुनाव से पूर्व शिवराज और उसकी भुखेरा जन पार्टी ने चुनावी खर्च निकालने और मोटी वसूली करने के लिए हर शासकीय शराब ठेके के दुकानदार को रु5 से 50 वसूली करवाना शुरू कर दी थी। बाद में जीत कर आई कांग्रेस की सरकार ने एक कदम आगे अपनी मोटी वसूली और कमाई के लिए प्रदेश को बर्बाद करने के लिए नाथ सरकार ने शराब के साथ में भी किया।

शराब की चुनाव से पहले की कीमतों में सीधा अधिकतम छपे हुए मूल्य से भी 20% अधिक वसूली की जा रही है। इसके बाद में भी उनकी तैयारी है। शासन को नगद राजस्व लाभ बढ़ाने, शराब की बिक्री बढ़ाने के लिए सभी पर्यटन केंद्रों पर प्रदेश में 2000 से ज्यादा शराब की दुकानें खोलने की नीच नीति पर काम किया जा रहा है ताकि हमारी युवा पीढ़ी जो भयंकर बेरोजगारी झेल रही है और सरकार को कोस रही है। शराब के नशे में डूब कर इन सत्ता धीश राक्षसों के पापों को भूल नशे में डूबी रहे।

उद्यानिकी विभाग में चल रहा है फर्जीवाड़े का तांडव

विकास खंड स्तर का अधिकारी 20 साल से बैठा उपसंचालक बन कर

जिनकी कोई जांच नहीं हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार, अधिकांश जिलों में मोटी कमाई के लिए प्रभारी

मध्यप्रदेश उद्यानिकी विभाग में वैसे तो अधिकांश कार्य, फलों के बाग, सब्जियां मसाले जड़ी बूटियां आदि की उपजें कागज के खेतों पर आंकड़ों की फसलें, लहलहाती रहती है। फिर इस उद्यानिकी विभाग के महा भ्रष्टों का नियंत्रण घोर भ्रष्ट जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के हाथ में होता है। जो जिले का सबसे बड़ा शासकीय डकैत होता है जो की 80 से ज्यादा योजनाओं में केंद्र का व राज्यों का धन हजम करता है।

भुखेरा जन पार्टी पार्टी के 15 साल के शासन में हर विभाग में हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार हुए उसमें से एक उद्यानिकी भी है। जहां पर सूक्ष्म सिंचाई, पोली हाउस भावांतर के नाम पर हर जिले में हर साल अनुदान का फर्जीवाड़े से सैकड़ों करोड़ हजम किया गया। तो दूसरी तरफ सूक्ष्म सिंचाई और पॉलीहाउस के नाम पर हर जिले में सैकड़ों किसानों के नाम से बैंकों से फर्जी ऋण निकाल कर अनुदान समायोजित कर हजम कर लिया गया और जब किसानों के पास उसके ऋण भुगतान की किस्तों के नोटिस आए तब किसानों को मालूम पड़ा।

यथार्थ में उद्यानिकी विभाग में मंत्री प्रधान सचिव जानबूझकर अपना मोटा धन हजम करके पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर अधिकारियों को बैठाते हैं, जो कि उस पद से 2-3 पद तक नीचे होते हैं। इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण प्रकरण है बुरहानपुर में बैठे या बैठाए गए आरबीएस तोमर का जो विकासखंड स्तर का उद्यानिकी अधिकारी है। परंतु प्राप्त जानकारी के अनुसार उसे जिले का उपसंचालक का प्रभार संभाले हुए 20 साल हो गए हैं। उसने वहां पर अरबों रुपए के घोटाले किए हुए हैं 20 साल से वह किसी को वहां पर बैठने नहीं दे रहा है। जिस दिन उसको हटाया गया वह अरबों रुपए के घोटाले निकलेंगे। जिसकी जांच होने पर अरबों रुपए के पिछले 20 साल में कि वह घोटाले सामने आएंगे।

विकासखंड स्तर का अधिकारी जिला स्तर पर डिप्टी डायरेक्टर बनकर बैठा हुआ है इसका पद वरिष्ठ उद्यानिकी विकास अधिकारी है। यही हाल गुना में बैठे पांडे का भी है जो कि वरिष्ठ उद्यान की अधिकारी है विकास खंड स्तर का परंतु इसने भी मोटा पैसा खर्च कर गुना में डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट पर बैठा हुआ है और उसने 16-17, 17-18, 18-19 में प्याज और लहसुन में भावंतर में पॉलीहाउस में सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं में भारी मोटा भ्रष्टाचार किया है और अपने मुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत वह अपने वरिष्ठों को धन बांट सबका मुंह बंद कर रखा है। यही हाल इंदौर संभाग के 8 जिलों का भी है।

धार में मंडलोई इंदौर में वास्केले, खरगोन में गिरवाल, झाबुआ में विजय सिंह, बड़वानी में अजय चौहान, खंडवा में राजू बड़वाया, अलीराजपुर में चौहान, गुना में पांडे बुरहानपुर वाले ने हर योजना में केंद्र व राज्यों की भारी भ्रष्टाचार किया है। भावांतर में लहसुन और प्याज की फसलों के लिए सरकार ने किसानों की लहसुन और प्याज की बाजार में खरीदी के भावों के अंतर का धन किसानों के खाते में जमा किया जाना था। परंतु इस की खरीद में वहीं फसल बार-बार लौटकर खरीदी बिक्री की जाती रही और सैकड़ों करोड़ का उप संचालक उद्यानिकी के माध्यम से मंडी सचिवों, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिलाधीश आदि ने मिलकर हर जिले में सैकड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार कर हजम किया. विधानसभाओं में भी भारी हल्ला मचा जांच की नौटंकी भी की गई परंतु जांच किसी की भी नहीं हुई और आसानी से धन हजम कर लिया गया। आखिर कमलनाथ सरकार पूर्व की भूखेरा जन पार्टी की सरकार की के समय के हर विभाग में बरसो से बैठे घोर भ्रष्टों जांच क्यों नहीं की जाती और उनका स्थानांतरण क्यों नहीं किया जाता।

म प्र गृह निर्माण मंडल लूटो और लुटाओ, जैसे चाहो खाओ

घोर भ्रष्ट कार्यपालन यंत्री सेवालय और श्रीवास्तव का स्थानांतरण रद्द

गैरकानूनी तरीके से 30 साल से गृह नगर में उपयंत्री से कार्यपालन यंत्री तक, समय माया की पहल और सैकड़ों शिकायत लोकायुक्त से लेकर शासन को की गई, के चलते मार्च में किया हुआ स्थानांतरण भोपाल से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार दिग्गी दानव के बेटे राजवर्धन सिंह मंत्री ने 1-1 रु करोड़ में रद्द कर दिया है। जैसा कि पूर्व मुमं आरोप लगाता है प्रदेश में सामने से शासन कमलनाथ का हो। परंतु पीछे से अपनी ऐतिहासिक भ्रष्ट शैली से दिग्गी दानव ही पूरी सरकार चला रहा है।पूर्णता सच ही है।

मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल में 30 साल से बैठे हुए मनोज से शिवाले और मनोज श्रीवास्तव जो एक ही जगह रहते हुए उपयंत्री से कार्यपालन यंत्री तक बन गए और वहां रहते हुए उन्होंने अरबों रुपए की संपत्ति इकट्ठी की। बड़ी जद्दोजहद के बाद उनका फरवरी में स्थानांतरण हो गया था परंतु वह आचार संहिता की आड़ लेकर बच गए और तब से इंदौर में ही जमे हुए हैं। इनका लोकायुक्त आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो इन सब को चाहिए कि उनकी संपत्तियों की जांच और उनके कार्यों की जांच की जाए।

इन्होंने पिछले 30 वर्षों में हजारों गृह निर्माण मंडल के हितग्राहियों से अरबों रुपए हजम किया। गृह निर्माण मंडल की सैकड़ों जमीनों प्लाटों मकानों को बाले बाले बेंचा। 90% कालोनियों सड़कों भवनों के रखरखाव रंगाई पुताई आदि का पैसा हजम करते रहे ये सूअर इनकी धर्म पत्नियों के साथ में अनेकों जीवन सहायिका हैं जिनको उन्होंने भवन संपत्तियों से अनुग्रहित किया है उन सब की जांच भी होनी चाहिए वैसे यह सहायिका वाला खेल उपायुक्त दौहरे का भी है इसकी धर्मपत्नी गवालियर में और सहायिकाएं इंदौर भोपाल में भी हैं। करोड़ों की संपत्तियों का मालिक है। इसकी भी जांच की जानी चाहिए। इंदौर में मध्य प्रदेश के ग्रामीण गृह निर्माण मंडल के शॉपिंग माल स्थित कार्यालय यथार्थ में पिछले 40 सालों से भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा बन चुका है। जिसके अंतर्गत 8 जिलों का नियंत्रण कर्ता अधिकारी उपायुक्त के साथ दो कार्यपालन यंत्री निर्माण विभाग जिसमें एक में मनोज शिवाले और एक मनोज श्रीवास्तव पिछले 35 सालों से उपयंत्री के रूप में भर्ती होकर, विद्युत संभाग भी है। मनोज शिवाले और मनोज श्रीवास्तव दोनों ने 1985 में अपने गृह नगर इंदौर के इसी विभाग मैं उपयंत्री के रूप में अपनी सेवाएं प्रारंभ की थी। पर अपने भ्रष्टाचार, जी हुजूरी के दम पर अपने गृह नगर में ही ये दोनों सहायक यंत्री, और वर्तमान में कार्यपालन यंत्री का पदभार संभाले है। जो कि पुर्णता: नियम विरुद्ध है। नियमानुसार कोई भी उपयंत्री किसी भी तरह से कार्यपालन यंत्री का नहीं कर सकताहै। दूसरी तरफ कोई भी अपने ही गृह नगर में 35 साल तक सेवायें एक ही स्थान पर उपयंत्री सहायक यंत्री कार्यपालन यंत्री बनकर कार्य कर रहा है। स्वाभाविक है, कि अपनी भ्रष्टाचार पूर्ण कार्यशैली से लूटो और लुटाओ के साथ अपने वरिष्ठ एवं भ्रष्ट अधिकारियों से लेकर मंडल के अध्यक्ष, प्रधान सचिव, मंत्री व खुरापाती नेताओं तक तन मन धन से धन व सुरा सुंदरी की पूर्ण समर्पण से सेवायें देने के कारण ही ना केवल यहां डटे हुए हैं, वरन पत्रकारों, अधिकारियों, नेताओं तक को अपने अवैध कृत्यों की शिकायत करने उंगली उठाने पर, इंदौरी नेताओं का नाम लेकर डराने धमकाने से भी नहीं चूकते। चूंकि ये घोर भ्रष्ट गृह निर्माण मंडल के न केवल धारकों वरन विभाग की भी सभी योजनाओं, भवनो और कालोनियों भारी लूटपाट का तांडव मचाकर प्लॉटों, फ्लेटों, दुकानों मकानों आदि के पंजीयन, बिक्री, आमंत्रण, नामांतरण, आदि में भारी जालसाजी कर वर्तमान में दोनों पिछले 34-35 सालों में लगभग 100 से 150 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। इनकी कई फ्लैटों और मकानों में इनकी सहायक अर्धांगिनीयां निवास कर रही है। जिनका उपयोग नेताओं मंत्रियों अधिकारियों को खुश करने में भी किया जाता है। इसलिए यह दोनों खुले में चिल्लाते हैं कि हम अपनी कमाई का 20-25% मंत्री, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, सांसद, विधायकों, पार्षदों, नेताओं, पत्रकारों, लोकायुक्त आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो, जैसे श्वानो को मासिक व यथा योग्य टुकड़े डालकर पालते हैं। इसलिए हमारा कोई कुछ उखाड़ बिगाड़ नहीं सकता। यही कारण है की घोर मक्कार और भ्रष्ट दिग्गी दानव के बेटे राजवर्धन सिंह ने धन लेकर इन दोनों का स्थानांतरण रद्द कर दिया।

भूखेरा जन पार्टी: मुफ्त में लुटा कर लूटते व खोखला करते रहे विद्युत कंपनियों को

विद्युत मंडल की सारी कंपनियों का समाप्त करो पुनः बनाओ म प्र विद्युत मंडल

सारी कंपनियों से बाहर करो डकैत आई ए एस अधिकारियों को विद्युत तकनीकी अधिकारियों को बनाओ अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक, साथ ही विभाग में आउटसोर्सिंग, ठेकेदारी, फ्रेंचाइजी व्यवस्था तत्काल खत्म करो, स्थाई कर्मचारियों, इंजीनियरो अधिकारियों की भर्ती करो। पुनः मंडल का नई सिरे से 15 वर्ष के कार्यकाल का अवलोकन कर रखरखाव व नवीनीकरण किया जाना चाहिए। 15 साल में की गई खरीद बिक्री रखरखाओ भ्रष्टाचार की जांच भी की जानी चाहिए और दोषियों को, नीचे से लेकर ऊपर तक दंडित भी किया जाना चाहिए।

जनता को सपने बांटते रहे बड़े विज्ञापन छपवा कर भ्रमित करते रहे और प्रदेश को हर तरीके से खोखला करते रहे। नदियों की रेत का 700 से ज्यादा डंपरों से व्यापार करते रहे, जो भी बीच में आया जैसे अनिल माधव दवे जैसे लोगों से लेकर आई ए एस, आइ पी एस से लेकर, एडीएम, खनन निरीक्षको से लेकर अधिकारियों तक कईयों को गुंडो के माध्यम से यमलोक भी पहुँचाया।

विद्युत मंडल को कंपनियों में परिवर्तित करने वाली 1999 से 2004 तक रही केंद्र की अटल सरकार के मंत्रियों जिसमें अरूण शौरी, प्रमोद महाजन जैसों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों से मोटा कमीशन खाकर सारी सरकारी कंपनियों, NTPC NHDC ONGC IOCL BPCL HPCL SAIL SBI BOI BOB, IRCC आदि सैकड़ों, सड़क परिवहन निगमों, सारे राज्य मार्गों की सड़कों को, आइल फेडरेशन के साल्वेंट प्लांटों, उद्योगों को विनिवेशीकरण की आड़ में हजारों करोड़ का खेल खेला गया।

विद्युत मंडल से कंपनियों में विभाजित करने का सबसे ज्यादा लाभ उठाया शिब्बू मामा ने, 50₹ कमीशन पर रु. 5से 7/- प्रति यूनिट की हजारों मेगावाट बिजली सौर व पवन ऊर्जा प्रतिदिन खरीदने के सौदे उन कंपनियों से ही किए जिनमें नेताओं और अधिकारियों का पैसा लगा हुआ था। उस बिजली की खबर दिखाने के लिए जो शासकीय ताप विद्युत गृह थे। जिसमें सारणी, बिरसिंहपुर पाली, खंडवा आदि के प्लांटों को जानबूझकर बेचने के लिए न्यूनतम उत्पादन कर घाटे में दिखा कर एक तरफ उसका कोयला बाले बाले बेच खाया तो दूसरी तरफ टाटा रिलायंस मोजर बेयर की महंगी विद्युत भी खरीदी की जाती रही जबकि जल विद्युत और ताप विद्युत के उत्पादन को अपने हिस्से का भी और राष्ट्रीय ताप विद्युत और राष्ट्रीय जल विद्युत कंपनियों से जो न्यूनतम लागत रुपए 50 पैसे से लेकर रु. 1 तक पर उपलब्ध थी उसे नहीं खरीदा गया जबकि उसमें सरकार का 51₹ पूर्व अधिकारी और 49 परसेंट कभी पहला अधिकार था यही हाल पूरे प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों के साथ में भी हुआ जिसमें 15 साल में विद्युत घोड़ो ग्वीडो पावर स्टेशनों से लेकर घरेलू और व्यावसायिक विद्युत

आपूर्ति के पुरानी मजबूत आभारी लाखों खंबो तक को निकाल कर बैच के खा लिया गया तो दूसरी तरफ पूरे प्रदेश के खंभों को बदलने के नाम पर हजारों करोड़ का कमीशन खाकर कंपनियों से ऐसे खंबे खड़े करवाएं जो लाइन खींचने से पहले ही पड़े हुए आया करते थे और आज भी खड़े खड़े हैं से लेकर जो विद्युत मंडल केवल मार्च अप्रैल और मई में हर वर्ष पूर्व मानसून तैयारी करता था और सारे वर्ष बिजली निर्बाध मिला करती थी वह मेंटेनेंस इन कंपनियों के महा धूर्त भारतीय प्रताड़ना सेवा के अधिकारियों द्वारा 75₹ जिसमें इंदौर का आकाश त्रिपाठी तक ने हजम कर लिया गया। फिर इन आई ए एस अधिकारियों से लेकर मंत्री मुख्यमंत्री को भी हजारों करोड़ का प्रतिवर्ष का कमीशन सबने डकारा। पर इसकी तरफ आमजन से लेकर बुद्धिजीवियों तक किसी की तब भी नहीं गई और अब भी नहीं जा रही।रखरखाव के नाम पर भी क्योंकि इन कंपनियों को घाटे में लाकर बड़े पूंजीपतियों को सौंपना है इसलिए जानबूझकर इन वितरण कंपनियों ने पूरी विद्युत मंडल की उत्पादन से लेकर वितरण तक की सरन चुरा को चौपट करने का काम इन हरामखोर आईएएस अधिकारियों को सौंप रखा है।

जिससे लोड सेटिंग से लेकर पुराने ट्रांसफार्मरों पर समय पर तेल पानी और परिवर्तन का कार्य भी 25% तक भी ढंग से और स्तरीय नहीं हुआ जिसका परिणाम शिवराज के जाते ही कांग्रेसी सरकार को भुगतना पड़ रहा है। बेशक ना केवल सभी वितरण कंपनियों के पास पर्याप्त उचित स्तर की ट्रांसफार्मर व पावर स्टेशनों से लेकर खंबो तक के रखरखाव के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं है।

दूसरी इसी के साथ 1990 के उपरांत मोटे कमीशन पर सेवाओं के आउट सोर्स करने कर्मचारी अधिकारियों के सेवानिवृत्त होने या मृत्यु होने पर पदों की भर्ती नहीं की गई इससे पूरे विद्युत मंडल की सारी कंपनियां आवश्यकता के स्टाफ से 30 से 40% स्टाफ के साथ काम करना उनके लिए मजबूरी बन गई है। स्वाभाविक सी बात है सारे गड्ढे एक साथ सामने आकर ज्यादा गहरे हो गए और चारों तरफ ऑन लाइन ट्रिपिंग, ट्रांसफार्मर का जलना आग लगना के कारण आपूर्ति बाधित होना सामान्य सी बात हो गई है। पर उसके पीछे सबसे बड़े कारण है भेड़िया झुंड पार्टी की लूट खसोंट और सब को बर्बाद करने की नीति। पर जनता तो गाली बकने के लिए नए मुख्यमंत्री कमलनाथ को ही निशाना बनाती और गालियां बकती है सच जानने की किसी को इच्छा भी नहीं है। हरामखोरों ने 15 साल में पूरी तबाही मचा दी हजारों करोड़ हर साल बिजली से लूटकर खाया मेंटेनेंस के नाम पर केवल फर्जी बाउचर लगाए जाते रहे। मंत्री मुख्यमंत्री शिवराज और वहां बैठे सूत्रों की फौज आईएएस अधिकारी जो कि प्रबंध संचालक कार्यपालक संचालक बनकर बैठते हैं। बिना बिजली की एबीसीडी नहीं आती थी वहां प्रबंध संचालक संचालक बनकर 15 साल तक पूरे प्रदेश की बिजली कंपनियों को लूटते रहे। विद्युत मंडल की अपने स्रोतों से जिसमें साडे 9000 मेगा वाट ताप विद्युत घरों से लगभग 7000 मेगावाट पनबिजली से प्राप्त हो रही है। इसके विपरीत 14000 मेगावाट बिजली सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जिसमें खुद का पैसा लगा हुआ था ताप जो बड़ी कंपनियों की थी बिना आवश्यकता 50% से 70% कमीशन पर 5.50 से 6.50 रुपए प्रति यूनिट की खरीदी की गारंटी दी गई और भुगतान किया जाता रहा जबकि उसकी आवश्यकता ही नहीं थी। उसके बदले में ढाई रुपए से तीन और चार रुपए प्रति यूनिट में बिजली दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान को बेची जा रही थी।

जो सरकारी संसाधनों से उत्पादन की जा रही थी और इस प्रकार जो घाटा हो रहा था। महंगी विद्युत वितरण कंपनियों को देकर उसकी भरपाई जनता से की जा रही है। शायद यह कहानी किसी को समझ में नहीं आई। कि किस प्रकार से भेडियो की झुंड पार्टी ने प्रदेश के विद्युत मंडल को कंपनियों में बदलकर लूटपाट मचाई।

अब जब पूरा खोखला हो गया तब कमलनाथ के हाथ सत्ता आई। वही भरी है अब सरकार को बदनाम करने और अपनी पोल खुलते देख कर जनता को लालटेन दिखा कर भ्रमित कर रहे हैं हरामखोर क्या नहीं लूटा नदियों से रेत निकाली 510 कोड का सॉफ्टवेयर साढे 500-600 करोड़ में बनवाएं।

90% तक धन हजम किया। ताई के लड़कों के पास बिल बनाने के ठेके प्रति बिल नही वरन बिल की राशि पर 0.1% के हिसाब से दिये थे। इसलिये वो दोनों शूकर 5से 10-20गुना के बिल बनाते थे।3-4- से 6माह के औसत और बाद में पुराने बिलों को बिना समायोजित किये इकठ्ठा बिल देते थे। ताकि उनका करोड़ों रुपये में भुगतान हो। यह अपनी लोकसभा वक्ता के बेटों की जालसाजी नहीं बताते। ये भेड़ियों की फ़ौज। लालटेन खरीदी, बड़े आंदोलन, फिर उसमे आये लोगों के भंडारे करने का, करोड़ो रुपये का खर्च उसी पैसे से हो रहा है। न जो जनता से पहले लूटा गया था।

जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो जनता कहां जाए

मोदी है, तो मुमकिन है। कहां हो? मोदी के अंध भक्तों

हिंदुओं के साथ एक कहावत बड़ी चरितार्थ होती है। वह है। सहारा के रेगिस्तान में पाया जाने वाला शुतुरमुर्ग पक्षी। जो तूफान आता हुआ देखकर अपनी गर्दन रेत में घुसेड़ लेता है। उसकी रेत में गर्दन घुसेड़ देने से तूफान आना तो नहीं रुकते। बल्कि जब जो भारी तूफान आता है उसके शरीर सहित उसको उठाकर बाहर गरम रेत के टीलों पर पटक के झुलसाकर खत्म कर देता है। यही सच इस दुनिया की सबसे सहस्त्रों वर्षों पुरानी और श्रेष्ठ ज्ञान का प्रकाश बिखेरने, भाषा, विज्ञान, गणित, खगोलशास्त्र, कृषि, आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त कर अतीन्द्रिय ज्ञान से भविष्य की गणनाएं करने वाली इस कौम का दुर्भाग्य यही है, कि उसे भविष्य में आने वाले तूफान को देख गर्दन रेत में घुसेड़ने में तो विश्वास है। परंतु तूफान की दिशा बदलने, बचने बचाने में विश्वास नहीं है। ये सहस्त्रों वर्षों से गुलाम इसलिए ही हैं कि यह घोर स्वार्थी, मक्कार, आलसी और स्वाभिमान हीन कौम को प्रकृति ने सरलता से सब कुछ दिया। इसलिये हत्यारों, आपराधिक, आतंकी मुगलों, अंग्रेजों के बाद ऐसे ही नेता अब हम पर शासन कर रहे हैं। यह ऐतिहासिक हाल और दुर्भाग्य हमारे हिंदुओं का ही है। जो सच से दूर हो, स्वाभिमान बेच गुलामों की जिंदगी जीने और मुफ्तखोरी करने में विश्वास रखता है।संयुक्त राष्ट्र और पूरी दुनिया चिल्ला रही है। कि हिन्दुओं जागो और अस्तित्व बचाओ। पर उसे तो सच पढ़ने से भी डर लगता है।

आप मेरे नहीं अपने, समाज के, गांव, जिले, प्रदेश और देश के सच से दूर हो। कहां तो भागेंगे।

ऐतिहासिक आपराधिक प्रवृत्ति के अमित शाह के गृहमंत्री बनने के बाद पुलिस वालों से मोटी वसूली के लिए दिए गए मौखिक आदेश में जब पुलिस वालों ने यह खुलेआम वसूली का खेल शुरू किया। तो चारों तरफ हर दिन पुलिस वालों की कुटाई पिटाई के वीडियो पूरे देश में आग की तरह फैल रहे हैं।

'मोदी है तो मुमकिन है।' जालसाजी से चुनाव जीता तो यह तो होगा ही अब आतंकवादी रोज 10-20 हमारे भारतीय सैनिकों को जो सेना सीमा सुरक्षा बल केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के होते हैं। मारे जा रहे हैं।

अभी सत्ता संभाले 40 दिन ही तो हुआ है। देखते चलिए । अभी और क्या क्या होगा?

गृहमंत्री खुद ही आपराधिक हत्यारा जाल साज डकैत रहा है डकैती डालने का पुलिस विभाग को पूरा छोड़ दिया है। जनता ऐसे बसूली बाज पुलिस वालों को पटक-पटक कर पिटाई कर रही है वर्दी फाड़ रही है और अमित शाह को चांटा जड़ रही है समझ में आ रहा है ना। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो जनता कहां जाए। पुलिस को ही जनता मार रही है। तो कौन पकड़ेगा, अपराधियों को। आतंकवादियों को। जिहादियों को।

उठो। हिन्दुओ सहस्त्रों वर्षों से गुलाम हिन्दुओ मत कहो, हमें क्या करना है? सरकार करेगी की, हिंदुओं चूड़ियां उतारो। अपनी, अपने परिवार की समाज की और देश की रक्षा करने अब कोई तुम्हारा नहीं जो तुम्हारे हितों का ख्याल रखेगा। एकत्रित हो आक्रमक बनो। और पुरुष के रूप में प्रकृति ने आपको अगर जन्म दिया है। तो उठो हे हिंदू वीरो अपने स्वर्णिम इतिहास को याद कर अपनी, परिवार, समाज और राष्ट्र की आंतरिक और बाहरी रक्षा के लिये मुश्कें कस कर तैयार रहो।

अंग्रेजों की रॉयल सोशल सर्विस के हिंदी संस्करण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी भी आजादी के पहले हिंदुओं हिंदू धर्म और उसकी महिलाओं को बचाने हेडगेवार से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक जोकि मुस्लिम लीग के साथ मिलकर पूर्व पश्चिम बंगाल सरकार में आजादी से पूर्व मंत्री था। ने भी हिंदुओं के बंगाल में कत्लेआम में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जब तक कांग्रेश रही तब तक हिंदुत्व के नाम पर उसने करोड़ो हिंदुओं को शाखाओं में सुबह से शाम तक जरूरत पड़ने राष्ट्रीयता, हिन्दूत्व, संस्कृति के नाम पर छला, उपयोग किया और निचौड़ा। जब से केंद्र में और राज्यों में उनकी सत्ता आई हिंदुत्व नाम मिटा और भुला दिया गया। वक्त आ गया है।मोदी अमित शाह और उनकी भेढ़िया झुंड पार्टी के लोगों को दिखा दो कि सत्ता और हिंदुओं से लूटा गया धन। तुम्हारे बाप की जागीर नहीं। जो कहीं पर भी लुटाओगे। देश को खोखला करोगे। देश के उद्योग धंधे धंधों को बर्बाद करोगे चीनी माल 25% कमीशन पर आयात करोगे। फिर भी उसी चीन से अपना जहाज AN32 गिरवाओगे। फिर भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उससे हाथ मिलाओगे।

रिजर्व बैंक कंगाल बनाओगे। उसका 280 टन सोना इंग्लैंड को गिरवी करोगे। हिन्दुओं जागृत हो। एकत्रित हो। संयुक्त राष्ट्र और पूरी दुनिया चिल्ला रही है। कि हिन्दुओं जागो और अस्तित्व बचाओ। पर उसे तो सच पढ़ने से भी डर लगता है। आप मेरे नहीं अपने, समाज के, गांव, जिले, प्रदेश और देश के सच से दूर हो। कहां तो भागेंगे।

अब तो हिंदूवादियों की सरकार है ना, मुस्लिम मदरसों छात्रों पुस्तकालयों को करोड़ों की मदद हिंदुओं को लूट कर मुस्लिमों को मोदी सरकार दे सकती है।

तो पाखंडी धूर्त मक्कार मोदी हिंदुओं का नोट वोट खाकर क्या एक सनातन धर्म की परंपरा को जीवित रखने और उसके साहित्य को प्रकाशित करने के लिए 100 200 करोड़ की मदद नहीं दे सकती।

वह मक्कार पाखंडी, लाखों-करोड़ की विदेशी यात्राओं में, अपने को महान सिद्ध करने रूस अमेरिका की यात्राओं, दोस्ती का दिखावा करने समयबाधित हथियारों का कबाड़ा खरीदने व अन्य तरीकों से बर्बादी कर चुका है।

उससे बोलिए ना। ईमेल भेजिये। उसको जब मुस्लिमों के मदरसे जो आतंकी संस्थाओं को पाल सकते हैं। और सरकार उनको सहायता दे सकती है।

तो गोरखपुर प्रेस तो बेचारी पिछली शताब्दी से ज्यादा समय से ही हिन्दू संस्कृति व साहित्य बचाने, प्रकाशित करने के कार्य में लगी है। RSS, भाजपा, उसका मु मंत्री योगी को जान और सुन मदद करनी चाहिये थी। यह कहानी पिछले 8 साल से क्यों और कैसे चल रही है।

समझो मूर्ख हिंदुओं मोदी अमित शाह आर एस एस और भाजपा इन सब का यथार्थ इस कहानी से समझो तुम्हें लूट कर, वक्त आने पर तुम्हें और तुम्हारा हित चाहने वाली संस्थाओं को कैसे कटोरा थामकर चौराहे पर खड़ा कर दिया जायेगा।

सभी विभागों में वर्षों से बैठे एक ही स्थान पर पदस्थ भ्रष्ट कर्मियों का करो स्थानांतरण

प्रदेश के सभी विभागों में 15 वर्ष से जमे भ्रष्टाचार के कीचड़ को साफ किया जाना अत्यधिक आवश्यक हो चुका है। स्थानांतरण, सभी विभागों के कर्मचारियों अधिकारियों में मस्तिष्क और शरीर में लगी हुई जंग को दूर करने के लिए आवश्यक है।सभी अधिकारियों कर्मचारियों को जो तीन-चार वर्षों से लेकर 20-20, 25-25 वर्षों में से एक ही स्थान पर और पद पर रहकर भ्रष्टाचार का तांडव कर रहे हैं। अधिकांश अधिकारी कर्मचारी से लेकर पंचायत सचिव तक करोड़ पतियों की लाइन लगी हुई है जिसका पता हाल ही में पड़े लोकायुक्त के छापों से मिल रहा है। ये कैसे छोटे-छोटे पदों पर बैठे कर्मचारी और अधिकारी करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। स्वाभाविक सी बात है शासन के नियमों कानूनों की आड़ में आमलोगों का, ठेकेदारों, विद्यार्थियों का पीड़ित जनता किसानों का भरपूर फायदा उठा कर भारी परेशान किया है। निर्माण कार्यों में सेवा कार्य में स्तरहीन सेवाएं देकर उन्होंने अपनी मोटी वसूली की है। अकेले खाद्य एवं औषधि विभाग में 155 से ज्यादा खाद्य व औषधि निरीक्षक 10 वर्षों से ज्यादा समय से एक ही स्थान पर जमे रहकर करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन चुके हैं। अपने स्थानांतरण रुकवाने के लिए 20-30 लाख रुपए तक देकर वे अंगद चारों तरफ लूटपाट का तांडव कर सरकारी नियमों कानूनों को की धज्जियां में उड़ाते हुए जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और खाद्य वस्तुओं के व्यापारियों उद्योगों फैक्ट्रियों से मासिक मोटी वसूली कर रहे हैं यही हाल औषधी निरीक्षकों का भी है इंदौर में जमा हुआ गोयल 10 साल से यही जमा हुआ है। जो हाल प्रदेश के खाद्य एवं औषधि विभाग का है ऐसे ही स्वास्थ्य विभाग में भी सैकड़ों डॉक्टर एक ही जिले में 10-10-20 वर्ष पूरे कर चुके हैं। आदिम जाति कल्याण विभाग में भी चारों तरफ घोर भ्रष्टाचार शासन की योजनाओं में चल रहा है।वहां पर भी अधिकांश कर्मचारी और अधिकारी वर्षों से कुंडली मारे हरिजन आदिवासियों के अधिकारों का हनन करते हुए करोड़ों रुपए के मालिक हैं। धार में बैठे सहायक बृजेंद्र पांडे जो कभी अपनी सीट पर उपलब्ध ही नहीं हुए। हर साल 15 से रु. 20000 करोड़ का आवंटन प्राप्त करते हैं। इनके अंतर्गत 500 से ज्यादा आदिवासी छात्रावास है यहां के अधिकांश कर्मचारी करोड़पति हैं। यहां निजी स्कूलों कॉलेजों में बांटी जाने वाली छात्रवृत्ति का भी चारों तरफ पूरे मध्यप्रदेश में भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। महिला बाल विकास में भी सैंकड़ों बाबू कर्मचारी और अधिकारी एक ही स्थान पर रहकर आंगनबाड़ियों का 90इ धन और आने वाली खाद्य सामग्री को हजम कर रहे हैं। मप्र लोक निर्माण, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ग्रामीण यांत्रिकी, नर्मदा घाटी विकास, गृह निर्माण, विद्युत, प्रदूषण मंडल, औद्योगिक केंद्रीय विकास निगम विभाग, सभी नगर निगमों पालिकाओं जनपदों में, विकास प्राधिकरणों में सैंकड़ों अनुरेखक उपयंत्री सहायक यंत्री कार्यपालन यंत्री वर्षों से जमे रहकर अपने से वरिष्ठ पदों के प्रभार में है बेशक यह सब मोटे धन के बदले में पूर्व के मंत्रियों और वर्तमान के मंत्रियों ने मासिक वसूली के साथ सौप रखे हैं। अधिकांश संभागों में, निगमों पालिकाओं प्राधिकरण में 10-10 वर्षों से ज्यादा समय से जमे हुए रहकर करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं का भी शीघ्र स्थानांतरण किया जाना चाहिए। कृषि व उद्यान की में भी अनेकों ग्रामीण कृषि उद्यानिकी विकास सहायक संचालक 5 वर्षों से लेकर 15 15 वर्षों से एक ही स्थान पर जमे रहकर भारी भ्रष्टाचार का तांडव कर रहे हैं। यही हाल पुलिस, आबकारी, वन विभाग के कर्मियों निरीक्षकों से लेकर उच्च अधिकारियों आदि का भी है। जो लंबे समय से जोड़ तोड़ कर एक ही स्थान पर जिम में रहकर शासन के नियमों को पलीता दिखाते हुए और अवैध वसूली करके अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं के भी शीघ्र स्थानांतरण किए जाने चाहिए ताकि शासन की सभी विभागों को सुचारू रूप से समय की पाबंदी के साथ चलाया जा सके और जनता को इससे राहत मिल सके।

जल संसाधन विभाग में 25 वर्षों से ज्यादा समय से खरगोन में डटे हुए घोर भ्रष्टाचार हरामखोर जाल साज अधीक्षण यंत्री भगोरा जो 1991 में सहायक यंत्री बनकर पदस्थ हुआ था। वहीं पर कार्यपालन यंत्री 2001 में और 2011 में अधीक्षण यंत्री बन गया जिसने हजारों करोड़ के भारी घोटाले किए अपने सहायक और कार्यपालन यंत्री काल में अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए वही पर मोटा धन देकर भाजपा के मंत्रियों को अधीक्षण यंत्री बन जाने के बाद अब बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर में भारी भ्रष्टाचार को अपने संरक्षण में कार्यपालन यंत्रियों के माध्यम से अंजाम दे रहा है। एजी ने लगभग 40 से ज्यादा ऐसे ठेकों में जिसमें इसने निविदाएं जारी की। बिना काम हुए भारी भुगतान किया और पुनः दो-दो तीन-तीन बार उनकी निविदाएं जारी कर दी गई। ऐसे उसने हजारों करोड़ के अनेकों घोटाले किए हुए हैं। उनकी जांच होने पर यह जो अभी इंदौर का मुख्य अभियंता बनने का सपना देख रहा है आसानी से भ्रष्टाचार के कांडों में सारी जिंदगी जेलों में करनी पड़ सकती है। इसी प्रकार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी में अनेकों कार्यपालन यंत्री 5 साल से ज्यादा समय से भारी भ्रष्टाचार करते हुए जमे हुए हैं। जिसमें सिंहस्थ के भ्रष्टाचारी नायक का.यं.उज्जैन का उदिया, धर्मेंद्र वर्मा, इंदौर का संजीव श्रीवास्तव है जो भारी धन खर्च कर एक ही स्थान पर 5 से ज्यादा वर्षों से जमे हुए हैं. इनका भी तत्काल स्थानांतरण कर कार्यकाल की जांच करवाई जानी चाहिये। यही हाल इंदौर उज्जैन के साथ ही प्रदेश के सभी नगर निगमों और पालिकाओं में और प्राधिकरणों का भी है जहां पर अनेकों इंजीनियर और अधिकारी 20- 25 वर्षों से ज्यादा समय से प्रतिनियुक्ति पर आकर भी अजगर की तरह कुंडली मारकर अरबों रुपए के भ्रष्टाचार की कमाई लूटकर और लुटाने के दम पर लिपटे हुए बैठे हैं।

म प्र के स्वास्थ्य विभाग में बैठे हुए 90इ डॉक्टर एक ही स्थान पर रहकर और नान प्रैक्टिस अलाउंस 25इ तक लेकर अपनी सेवाएं निजी अस्पतालों में दे रहे हैं और मोटी कमाई कर रहे हैं इनको भी तितर-बितर किया जाना आवश्यक है यही हाल शिक्षा विभाग के महाविद्यालय और स्कूली शिक्षा विभाग का भी है अनेकों शिक्षकों ने एक ही जगह पर रह कर अपनी व अन्य कोचिंग संस्थानों मे सेवाएं दे रहे है। और मोटी कमाई कर रहे हैं इन्हें भी कम से कम 300 किमी दूर स्थानांतरित किया जाना चाहिए पूरे प्रदेश में।

www.samaymaya.com की साइट से समाचार पत्र की पीडीएफ डाउनलोड कर सोशल मीडिया पर अपने मित्रों को भेज सकते हैं।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक- अजमेरा एस.पी. कुमार द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13 प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 299, अम्बेडकर नगर, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित।
भोपाल प्रतिनिधि- एस.के. भारद्वाज मो. 9074551045, इंदौर कार्यालय- 0731-2530859, मोबा. 9300755803